Page-01_Layout 1 3/8/2025 2:19 AM Page 1

■ वर्ष-17 ■ अंक-48 ■ पृष्ठ-8 ■ मूल्य : 1 रुपए

नई दिल्ली, शनिवार, 8 मार्च, 2025

newdibyabharat@gmail.com

जेपी नड्डा ने किया एम्स बिलासपुर में पीईटी-सीटी और स्पेक्ट... पृष्ठ-3

दिव्य भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए केंद्र और राज्यों का... पृष्ठ-7

संक्षिप्त

आईएफएस अधिकारी ने बिल्डिंग से कूदकर दी जान

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में स्थित विदेश मंत्रालय के आवासीय परिसर में भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के एक अधिकारी ने शुक्रवार सुबह कथित तौर पर अपने आवासीय भवन से कूदकर आत्महत्या कर ली। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने आईएफएस अधिकारी के निधन पर एक बयान जारी किया है। मंत्रालय ने शोक की इस घड़ी में परिवार की निजता का सम्मान करते हुए आगे की जानकारी जारी नहीं की है।

गृहमंत्री ने विश्वेशतीर्थ मेमोरियल अस्पताल का किया उद्घाटन

बेंगलुरु, (हि.स.)। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु के मराठाहल्ली में नवनिर्मित विश्वेशतीर्थ मेमोरियल अस्पताल का शुक्रवार को उद्घाटन किया। अस्पताल का संचालन श्रीकृष्ण सेवाश्रम ट्रस्ट करता है। इस अवसर पर शाह ने ट्रस्ट के सामाजिक कार्यों की प्रशंसा की। इस अस्पताल की क्षमता 150 बेड की है। इसका उद्देश्य अत्याधुनिक उपचार प्रणालियों के साथ गरीब और कमजोर लोगों का सस्ता एवं अच्छा इलाज करना है। यह अस्पताल गरीबों के लिए बड़ा सहारा बनेगा। इस अस्पताल का निर्माण दो एकड़ क्षेत्रफल में किया गया है, जिस पर कुल 60 करोड़ रुपये की लागत आयी है।

काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी : योगी

आलोक पाण्डेय

- बरसाना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रंगोत्सव का किया शुभारंभ
- मुख्यमंत्री ने बरसाना में श्री लाडली जी महाराज मंदिर में किया दर्शन पूजन
- बोले योगी, ब्रज भूमि श्रद्धा की भूमि, होली का त्यौहार एकता का सूत्र

मथुरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक दिवसीय दौरे पर मथुरा के बरसाना में 'रंगोत्सव 2025' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि काशी और अयोध्या के कायाकल्प के बाद अब मथुरा और ब्रज भूमि के विकास का समय आ गया है। बरसाना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने श्री लाडली जी महाराज मंदिर में दर्शन-पूजन किया और फूलों व लड्डूमार होली के जरिए रंगोत्सव की शुरूआत की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 5 हजार साल से भारत की सनातन संस्कृति को ऊर्जा देने वाली यह ब्रज भूमि श्रद्धा और आस्था की धरा है। इसके कण-कण में श्री राधा और श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि यहां काशी, अयोध्या और मथुरा, ये तीनों तीर्थ स्थल सनातन एकता के प्रतीक के रूप में मौजूद हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विरासत और विकास की नई परंपरा स्थापित हुई है, जिसका परिणाम हाल ही में संपन्न प्रयागराज महाकुम्भ के भव्य आयोजन के रूप में देखने को मिला। उन्होंने कहा कि जो जितना सनातन धर्म के खिलाफ बोलता था, अफवाह फैलाता था और तर्कहीन बातें करता था, उन्हें सनातन धर्मावलम्बियों ने महाकुम्भ के जरिए करारा जवाब दिया है। महाकुम्भ सनातन धर्म का दुर्लभतम क्षण बन गया है।

सीएम योगी ने कहा कि होली आपसी सद्भाव और दूरियों को मिटाने का त्योहार है। महाकुम्भ ने जहां दुनिया को एकता का संदेश दिया, वहीं होली इसे और मजबूत करती है। उन्होंने बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लठ्ठमार होली और लड्डूमार होली का जिक्र करते हुए सनातन धर्म की अद्भुत परंपराओं की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में ब्रज भूमि के विकास के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि करोड़ों की योजनाओं के साथ बरसाना को विकास से जोड़ा जा रहा है। पहली बार बरसाना में रोपवे की सुविधा शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि महाकुम्भ सकुशल सम्पन्न होने के बाद अब फुरसत मिली है। काशी, अयोध्या, प्रयागराज, मां विंध्यवासिनी धाम के विकास के उपरांत अब बारी इसी पुण्य भूमि की है। सीएम ने आश्वस्त किया कि मथुरा, बरसाना, ब्रजभूमि के विकास के लिए कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि वह होली के अवसर पर श्री राधारानी जी के श्रीचरणों में इसी निवेदन के साथ पहुंचे हैं। उन्होंने दिल्ली में रामभक्तों की सरकार आने का जिक्र करते हुए यमुना के संरक्षण का वादा दोहराया। सीएम ने कहा कि अब यमुना मइया भी गंगा मां की तरह निर्मल और अविरल होंगी।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने संतों का सम्मान किया और देश-दुनिया से आए लोगों को होली व रंगोत्सव की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि बरसाना ब्रह्मा, नंदगांव शिव और गोवर्धन विष्णु जी का प्रतीक है। यह ब्रज भूमि हर सनातन धर्मावलंबी के लिए आशीर्वाद का केंद्र है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार सुरक्षा, विकास और समृद्धि की गारंटी है। होली के इस पावन अवसर पर ब्रज भूमि के विकास को नई गति मिलेगी। सीएम ने इससे पहले श्री लाडली जी महाराज के मंदिर में दर्शन पूजन कर प्रदेश के कल्याण की कामना की।

विकसित भारत की यात्रा में पौष्टिक भोजन की बड़ी भूमिका : प्रधानमंत्री

रमाकान्त पाण्डेय

- अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रेरक महिलाएं संभालेंगी प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया अकाउंट
- प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों के गरीबी हटाओ के नारे को लेकर साधा निशाना

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को विकसित भारत की यात्रा में पौष्टिक भोजन की भूमिका को अहम बताया और कहा कि हमारा लक्ष्य कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं से मुक्ति के लिए देश के प्रत्येक परिवार को पर्याप्त पोषण देने का है।

प्रधानमंत्री गुजरात में सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान देश के खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिशन में एक उल्लेखनीय कदम है। उन्होंने कहा कि सूरत अनेक मामलों में गुजरात के साथ ही देश का एक अग्रणी शहर है। सूरत आज गरीब, वंचित को भोजन और पोषण की सुरक्षा देने में आगे निकल रहा है।

मोदी ने कहा कि यह संतृप्ति अभियान तुष्टीकरण की भावना को छोड़कर संतुष्टीकरण की भावना को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि सूरत में चलाया जा रहा यह संतृप्ति अभियान गुजरात के अन्य जिलों और देश के शेष राज्यों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। उन्होंने कहा कि जब सरकार ही लाभार्थी के दरवाजे पर जा रही है तो कोई छूटेगा कैसे और जब कोई छूटेगा नहीं तो कोई रूठेगा कैसे। जब सोच ये हो कि हमें सब तक लाभ पहुंचाना है, तो ठगने वाले दूर भाग जाते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले मैंने देश की नारी शक्ति से अपनी सफलताओं को अपनी उपलब्धियों को, अपने जीवन की प्रेरणादायी यात्रा को नमो ऐप पर शेयर करने का आग्रह किया। अनेक बहनों-बेटियों ने नमो ऐप पर अपनी गाथाएं शेयर की हैं। कल महिला दिवस है और कल महिला दिवस के अवसर पर मैं अपना सोशल अकाउंट ऐसी ही कुछ प्रेरणादायी बहनों-बेटियों को सौंपने जा रहा हूं।

उन्होंने कहा, मुझे संतोष है, हमारी सरकार गरीब की साथी बनकर हमेशा उसके साथ खड़ी है। कोविड काल में जब देशवासियों को सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई। ये दुनिया की सबसे बड़ी और अपने आप में एक अनूठी योजना है, जो आज तक चल रही है।

प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों के गरीबी हटाओ के नारे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले गरीबी हटती ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते दशक में पूरे देश में हमने गरीब को सशक्त करने के लिए मिशन मोड पर काम किया। गरीब के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बनाया गया ताकि उसे किसी के सामने भी हाथ फैलाने की नौबत न आए। पक्का घर, शौचालय, गैस कनेक्शन, नल कनेक्शन हो इससे गरीबों को नया आत्मविश्वास मिला। उन्होंने कहा कि बीमा का एक सुरक्षा कवच गरीब परिवार को दिया गया। पहली बार करीब 60 करोड़ भारतीयों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया। इसके अलावा हमारी सरकार ने गरीब को, निम्न मध्यम वर्ग को बीमा का सुरक्षा कवच भी दिया।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस स्त्री शक्ति की उपलब्धियों और योगदान का सम्मानित करने का अवसर : राष्ट्रपति

नई दिल्ली, (हि.स.)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा कि यह स्त्री शक्ति की उपलब्धियों और योगदान का सम्मानित करने का अवसर है।

राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी बहनों और बेटियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस स्त्री शक्ति की उपलब्धियों और देश तथा समाज में उनके अद्वितीय योगदान को सम्मानित करने का अवसर है। महिलाएं हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र की नींव भी होती हैं। महिलाओं ने प्रतिकूलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए भी विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अपनी पहचान बनाई है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अभी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। आइए हम सभी एक ऐसे समाज का निर्माण करने का संकल्प लें जहां हर महिला सुरक्षित महसूस करे और उसे आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें। राष्ट्रपति ने कहा कि मैं सभी सफल महिलाओं को बधाई देती हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूं।

औरंगजेब का गुणगान करने वाले ही कर रहे वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध : सुधांशु त्रिवेदी

अहमदाबाद, (हि.स.)। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्य सभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय कमलम में कहा कि जो लोग वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं, वे राष्ट्र को सभी विषयों में राष्ट्रशक्ति को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के आर्किटेक्ट सरदार वल्लभभाई पटेल गुजरात के थे और वन नेशन को अमृतकाल में नई ऊंचाई पर ले जाने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी गुजरात के हैं।

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो लोग यह कहते हैं कि भारत कभी एक देश था ही नहीं, देश को मुगलों, अंग्रेजों और औरंगजेब ने बनाया, वे लोग ही वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हैं। ये विरोध करने वाले लोग कभी राम मंदिर नहीं गए, वे महाकुंभ में भी स्नान करने नहीं गए, वे औरंगजेब का गुणगान कर रहे हैं, वे लोग ही इस मुद्दे पर राजनीति कर विरोध कर रहे हैं।

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो लोग देश को टुकड़े-टुकड़े में रखना चाहते हैं, वे ही देश में टुकड़े-टुकड़े में चुनाव करवाना चाहते हैं जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सभी वस्तुओं को एकता के सूत्र में जोड़ कर विकसित भारत के संकल्प को साकार करना चाहते हैं।

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज सुखद सहयोग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 41 हजार दिव्यांग भाई-बहनों को हर महीने 5 किलो अनाज देने की योजना की शुरूआत की। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए की सरकार देश के हर वर्ग को सशक्त, मजबूत और राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध और प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है। अगर यह त्योहार बहुत जल्दी आ गया तो काम में कई बाधाएं आएंगी, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के त्योहार को नियमित-व्यवस्थित और देश के स्वास्थ्य के सुचारू संचालन के लिए यह धारणा दी है। इस विचार का विरोध करने वाले लोग वो लोग हैं जिन्होंने भारत में हर नए बदलाव का विरोध किया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुद्रा योजना शुरू होने पर भी विरोध किया था और कहा था कि इतने सारे खाते नहीं खुल सकते, डेबिट नहीं हो सकते, जीएसटी का विरोध किया, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि भारत में डिजिटलीकरण नहीं हो सकता।

पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बर ने संसद में बयान दिया कि भारत के लोग कम पढ़े-लिखे हैं, टैक्स की आदत कम है इसलिए भारत में डिजिटलीकरण करना संभव नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता की शक्ति और समझ पर पूरा भरोसा है, जिसके कारण आज जीएसटी का काम अच्छे से चल रहा है। भारत डिजिटलीकरण में विश्व में अग्रणी बन गया है और दुनिया का 41 प्रतिशत डिजिटलीकरण भारत में होता है, अमेरिका और चीन को मिला दें तो भी भारत पहले स्थान पर है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए जरूरी है, कि वन नेशन वन इलेक्शन व्यावहारिक, राजनीतिक, संवैधानिक और सामाजिक संदर्भ में जरूरी है।

रक्षा मंत्री ने दुनिया का चक्कर लगाने निकलीं दो महिला नौसैनिकों से वार्ता कर हौसला बढ़ाया

नई दिल्ली, (हि.स.)। आईएनएसवी तारिणी पर सवार होकर दुनिया का चक्कर लगाने निकलीं नौसेना की दो महिला अधिकारियों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर बातचीत करके उनका हौसला बढ़ाया। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए इस समय अपने साहसिक अभियान के चौथे चरण में हैं और 01 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन पहुंचेंगी। दोनों महिलाएं 43,300 किमी. की यात्रा पूरी करके 25 मई तक गोवा लौटेंगी।

नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने पिछले साल 02 अक्टूबर को गोवा से इस ऐतिहासिक अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए भारतीय नौसेना के पोत तारिणी पर सवार होकर ऐतिहासिक समुद्री यात्रा पर निकलीं हैं। दुनिया का चक्कर लगा रही नौसेना की महिला अधिकारियों से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री ने बातचीत की। उन्होंने हौसला बढ़ाते हुए कहा कि दुनिया का चक्कर लगाने की अपार चुनौती वाली उनकी साहसी यात्रा नारी शक्ति की एक मिसाल है। हजारों समुद्री मील की यात्रा करते हुए कठिन समुद्री परिस्थितियों की लंबी अवधि के दौरान उनका अटूट शांत व्यवहार और सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण आज की महिलाओं की असाधारण क्षमताओं का उदाहरण है।

इस बातचीत ने सशस्त्र बलों में लैंगिक समावेश को बढ़ावा देने और समुद्री अभियानों में महिलाओं के उल्लेखनीय योगदान का जश्न मनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री ने चालक दल के साहस और समर्पण को सराहा।उन्होंने दुनिया के सबसे अलग-थलग जलक्षेत्र को पार करने और सबसे खतरनाक जल निकायों में से एक ड्रेक्स पैसेज के माध्यम से नौकायन करने के लिए बधाई दी। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में महिलाओं की अमूल्य भूमिका को स्वीकार करके रक्षा क्षेत्र में महिलाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए सरकार की ओर से भरोसा दिलाया।

Page-02_Layout 1 3/8/2025 2:20 AM Page 1

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को 'जन औषधि दिवस' के मौके पर अशोक विहार में जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया।

दिल्ली में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को लागू करेगी सरकार : रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को जन औषधि दिवस के अवसर पर अशोक विहार स्थित जन औषधि केंद्र का दौरा किया। इस अवसर पर रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार पूरे शहर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) को लागू करेगी। साथ ही उसके तहत पूरी दिल्ली में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य दिल्ली के लोगों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराना है।

इस अवसर पर पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि आज जन औषधि दिवस के अवसर पर हमने दिल्ली में अशोक विहार में स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का दौरा कर व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार के कारण दिल्ली में हम प्रधानमंत्री जन औषधि योजना को लागू नहीं कर पाए लेकिन हमारी सरकार इस लाभकारी योजना को दिल्ली में लागू करेगी ताकि दिल्ली के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं और चिकित्सा सम्बन्धी सामग्री काफी कम कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना से आम जनता, विशेष रूप से गरीब लोगों को लाभ मिलता है और कैंसर, शुगर जैसी बीमारियों की दवाइयां काफी कम कीमत में उपलब्ध होती हैं। साथ ही महिलाओं के लिए इन केन्द्रों में सेनेटरी नैपकिन मात्र एक रुपये में उपलब्ध हैं ताकि महिलाओं को एक स्वच्छ और स्वस्थ जीवन मिल सके।

मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारी सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सभी सरकारी अस्पताल के 500 मीटर के दायरे में कम से कम एक जन औषधि केंद्र स्थापित करेगी, ताकि मरीजों को अच्छी और सस्ती दवाइयां उपलब्ध की जा सकें। ये जन औषधि केंद्र ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50-70 फीसद कम कीमत पर जनता को डब्ल्यूएचओ प्रमाणित दवाइयां और चिकित्सा सम्बन्धी वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं। बहुत सारी दवाइयां 90 फीसद तक कम कीमत पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त वे जरूरत पड़ने पर आपातकालीन स्थिति में स्थानीय दवा खरीद की सुविधा देकर सरकारी अस्पतालों की सहायता भी करेंगे।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद करते हुए बताया कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) का कार्यान्वयन सभी नागरिकों के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाने और रोगियों पर वित्तीय बोझ को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

दिल्ली विधानसभा डिजिटल परिवर्तन की ओर अग्रसर, 'नेवा' होगा लागू

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करके विधानसभा में नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) को लागू करने पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर नेवा टीम का नेतृत्व अतिरिक्त सचिव एवं मिशन लीडर (नेवा) डॉ. सत्य प्रकाश ने किया।

बैठक के दौरान नेवा टीम ने एप्लिकेशन की प्रमुख विशेषताओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी। नेवा एक एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में कार्य करेगा, जो सभी विधायी कार्यों को कागज रहित और डिजिटल रूप से संपन्न बनाएगा।

इसके अंतर्गत सूचनाओं का प्रस्तुतीकरण, मंत्रीगत उत्तर, विधायी कार्यवाही, चर्चाएं, समिति रिपोर्ट और डिजिटल लाइब्रेरी तक पहुंच जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह पहल एक आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी विधायी प्रणाली की दिशा में एक बड़ा कदम है। परियोजना की त्वरित प्रगति पर बल देते हुए अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसके 100 दिनों के भीतर सफल क्रियान्वयन का निर्देश दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वन इंडिया, वन एप्लिकेशन दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा कि सभी विधानसभाओं में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे कार्यों की सुगमता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पिछले प्रशासन की उदासीनता और निजी परामर्शदाताओं तथा विक्रेताओं से जुड़ी असफलताओं के कारण ई-विधान परियोजना पिछले एक दशक से लंबित थी। दिल्ली विधानसभा अब पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस परियोजना को तेजी से पूरा करने की दिशा में अग्रसर है।

बायो-मेडिकल कचरे का सही प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी : सिरसा

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि बायो-मेडिकल कचरे का सही प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इसी क्रम में उन्होंने शुक्रवार को बायो-मेडिकल वेस्ट प्रबंधन जागरूकता कार्यशाला का उद्घाटन किया। यह कार्यशाला दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और सेंटर फॉर ऑक्यूपेशनल एंड एनवायरनमेंटल हेल्थ (सीओईएच) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। दिल्ली सचिवालय के ऑडिटोरियम में हुई इस कार्यशाला में सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बायो-मेडिकल कचरा प्रबंधन से जुड़े नियमों की जानकारी देना, उचित तरीके से निस्तारण को बढ़ावा देना और अस्पतालों को प्रभावी कचरा प्रबंधन नीतियां अपनाने के लिए प्रेरित करना था। इस दौरान बायो-मेडिकल कचरे के निपटान से जुड़े दिशानिर्देशों, महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और सरकार द्वारा लागू नियमों पर चर्चा की गई। अपने सम्बोधन में मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा जिम्मेदार तरीके से कचरे के निपटान के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बायो-मेडिकल कचरे का सही प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। सरकार इस दिशा में अस्पतालों का पूरा सहयोग कर रही है, और इस तरह की कार्यशालाएं उन्हें जिम्मेदारी से कचरे के निपटान की प्रक्रिया अपनाने के लिए मार्गदर्शन देंगी। कार्यशाला के दौरान यह बात सामने आई कि सारा बायो-मेडिकल कचरा हानिकारक नहीं होता लेकिन यदि हानिकारक और गैर-हानिकारक कचरे को अलग-अलग नहीं किया जाए, तो गैर-हानिकारक कचरा भी हानिकारक बन सकता है। यह न केवल पर्यावरण बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। इसलिए मंत्री ने वैज्ञानिक तरीके से बायो-मेडिकल कचरे के उचित छंटाई, संग्रहण और निस्तारण की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि स्वास्थ्यकर्मियों और पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके। कार्यशाला के दौरान बताया गया कि दिल्ली ने पर्यावरण प्रबंधन में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। सरकार द्वारा निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, कचरा प्रबंधन नीतियां और सतत उपायों को बढ़ावा देने जैसे कई प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली में वर्तमान में स्वास्थ्य संस्थानों से रोज लगभग 31 मीट्रिक टन बायो-मेडिकल कचरा उत्पन्न होता है। इसकी संभावित हानिकारक प्रकृति को देखते हुए, बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के तहत सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। दिल्ली में वर्तमान समय में दो बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट केंद्र संचालित हैं, जिनकी कुल क्षमता 62.8 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। इन केंद्रों की मदद से बायो-मेडिकल कचरे को नियंत्रित और पर्यावरण-सुरक्षित तरीके से निस्तारित किया जाता है। बायो मेडिकल वेस्ट कार्यशाला में इस बात पर चर्चा कि गई कि अनुचित तरीके से बायो-मेडिकल कचरे का निपटान करने से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसके समुचित निस्तारण नहीं होने से वायु प्रदूषण के साथ साथ वाटर पॉल्यूशन की समस्या भी बढ़ सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए संबंधित संस्थानों की नियमित निगरानी, समय-समय पर ऑडिट और बायो मेडिकल निस्तारण केंद्रों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। इस कार्यशाला के दौरान बेहतरीन बायो-मेडिकल वेस्ट प्रबंधन करने वाले 20 सरकारी अस्पतालों को सम्मानित किया गया।

आज का राशिफल

मेष राशि-धन का व्यय संभव, तनावपूर्ण वार्ता से बचिये, कार्य समय पर निपटा लें।

वृष राशि-अधिकारियों के समर्थन से सफलता, कार्य कुशलता से संतोष अवश्य होगा।

मिथुन राशि-चिन्तायें कम होंगी, सफलता के कार्य जुटायें, शुभ समाचार अवश्य मिलेगा।

कर्क राशि-बड़े-बड़े लोगों से मेल-मिलाप होगा, सुख-समृद्धि के साधन बनेंगे।

सिंह राशि-स्त्री वर्ग से हर्ष-उल्लास होगा तथा भोग-ऐश्वर्य की प्राप्ति अवश्य होगी।

कन्या राशि-प्रतिष्ठा बाल-बाल बचे, संघर्ष से अधिकार प्राप्त होंगे, समय का ध्यान रखें।

तुला राशि-प्रत्येक कार्य बाधा युक्त रखें, स्थिति सामर्थ पूर्ण होगी, रुके कार्य अवश्य बनेंगे।

वृश्चिक राशि-कुटुम्ब और धन की इच्छा बनेगी, परिश्रम से सोचे कार्य अवश्य बनेंगे।

धनु राशि-भावनायें विक्षुब्ध रहेंगी, दैनिक कार्यगति मंद रहेगी, सामाजिक कार्य में सहयोग करेंगे।

मकर राशि-तनाव, क्लेश व अशांति, धन का व्यय, सामाजिक खिन्नता अवश्य बनेगी।

कुंभ राशि-कार्य कुशलता से संतोष, व्यवसायिक समृद्धि के साधन जुटायेंगे, कार्य बनेंगे।

मीन राशि-कुटुम्ब के कार्यों में समय बीतेगा, हर्षप्रद समाचार अवश्य ही मिलेगा।

-अम्बुजा तिवारी

शादी से पूर्व परामर्श के लिए 'तेरे मेरे सपने' सेंटर खोलेगा राष्ट्रीय महिला आयोग, कल से होगी शुरुआत

नई दिल्ली, (हि.स.)। विवाह से पूर्व परामर्श के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग एक अनूठी पहल करने जा रहा है। आयोग आठ मार्च यानि अतंरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शनिवार को देश के नौ राज्यों में विवाह पूर्व परामर्श के लिए तेरे मेरे सपने नाम से सेंटर की शुरूआत कर रहा है।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने शुक्रवार को यहां एक प्रेसवार्ता में बताया कि कल से इस नई पहल की शुरूआत 9 राज्यों में 21 सेंटर के साथ हो रही है। सफल विवाह के लिए दो जोड़ों को इस रिश्ते के तमाम पहलुओं को जानना आवश्यक होता है। विवाह सिर्फ दो लोगों तक ही सीमित नहीं होता बल्कि उसमें दो परिवार शामिल होते हैं। कई सामाजिक पहलू होते हैं, जिसे समझा जाना चाहिए। खुशहाल वैवाहिक जीवन हो, इसके लिए अगर शादी से पहले ही दोनों लोगों को परामर्श दिया जाए तो इसे एक सफल योजना कहा जा सकता है। इसी सोच के साथ आयोग परामर्श केन्द्र खोलने जा रहा है। इसके लिए दिल्ली में परामर्शकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है।

विजया रहाटकर ने बताया कि तेरे मेरे सपने केन्द्र को स्थापित करने से पहले पिछले महीने पुणे में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से विभिन्न विषयों के परामर्शदाताओं ने भाग लिया था। इन केन्द्रों में क्या क्या विषय लिये जा सकते हैं और परामर्शदाताओं के लिए क्या क्या विषय हो सकते हैं उस पर बारीकी से विचार किया गया। एक सिलेबस तैयार किया गया है, जिसे महिला दिवस पर केन्द्रों में जारी किया जाएगा। इन केन्द्रों पर सलाह प्रदान करने वालों को नई दिल्ली में दो दिवसीय सम्मेलन में सिलेबस के साथ ट्रेनिंग दी जा चुकी है। यह सरकार की सहायता से संचालित किया जाएगा।

विजया रहाटकर ने बताया कि यह केन्द्र 9 राज्यों में खोले जाएंगे। इसमें राजस्थान(बीकानेर, उदयपुर), मध्य प्रदेश(भोपाल), महाराष्ट्र (नासिक, जालना, लातूर, गोरेगांव) हरियाणा (गुरुग्राम), ओडिशा, नई दिल्ली, तिरुवंतपुरम शामिल हैं। इसके साथ आवश्यकता के अनुसार इसे विस्तारित किया जाएगा। इन केन्द्रों के प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग और पैम्पलेट वितरित किए जाएंगे। यह सेंटर जिला कलेक्टर के माध्यम से खोले जाएंगे। आने वाले दिनों में इसके बारे में कालेज में भी सेमिनार किए जाएंगे।

आईआईटी दिल्ली 22 को यूजी-पीजी छात्रों के लिए अन्वेषण कार्यक्रम करेगा आयोजित

नई दिल्ली, (हि.स.)। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली आगामी 22 मार्च को अपने हौजखास परिसर में अन्वेषणः इनोवेशन एंड एक्सप्लोरेशन एक्रॉस डिसिप्लिन नामक एक कार्यक्रम आयोजित करेगा। यह कार्यक्रम विशेष रूप से यूजी और पीजी छात्रों के लिए है जो आईआईटी दिल्ली में उच्च शिक्षा या शोध करने में रुचि रखते हैं।

आईआईटी दिल्ली में अकादमिक डीन प्रो. नारायणन डी. कुरुर ने शुक्रवार को कहा कि यह आईआईटी दिल्ली की एक अनूठी पहल है, जो स्नातकोत्तर और पीएचडी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के इच्छुक स्नातक और परास्नातक छात्रों को आईआईटी दिल्ली में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक जीवन की झलक पाने का अवसर प्रदान करती है।

सूडोकु नवताल- 7363

कठिनतम

				1			6	
					5			
2		3	9			8		
6							5	
			8		3			
	1							4
		7			1	3		9
			2					
	5			6				

Jagrutidaur.com, Bangalore

- *प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.*
- *प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.*
- *पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते .*
- *पहेली का केवल एक ही हल है.*

सूडोकु नवताल -7362 का हल

7	6	8	2	1	9	3	4	5
2	1	5	6	3	4	8	7	9
3	4	9	5	7	8	6	1	2
5	7	4	8	6	1	9	2	3
9	2	1	3	4	5	7	8	6
8	3	6	7	9	2	1	5	4
1	5	3	4	8	5	2	9	7
4	9	7	1	2	3	5	6	8
6	8	2	9	5	7	4	3	1

दैनिक पंचांग

8 मार्च 2025 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

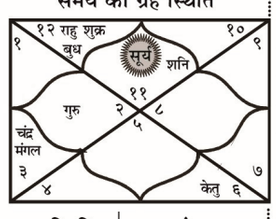

ग्रह स्थिति		लग्नारंभ समय	
सूर्य	कुंभ में	मीन	06.39 बजे से
चंद्र	मिथुन में	मेष	08.09 बजे से
मंगल	मिथुन में	वृष	09.49 बजे से
बुध	मीन में	मिथुन	11.47 बजे से
गुरु	वृष में	कर्क	14.01 बजे से
शुक्र	मीन में	सिंह	16.17 बजे से
शनि	कुंभ में	कन्या	18.29 बजे से
राहु	मीन में	तुला	20.40 बजे से
केतु	कन्या में	वृश्चिक	22.54 ब.से.
राहुकाल	9.00 से 10.30 बजे तक	धनु	01.10 बजे से
		मकर	03.15 बजे से
		कुंभ	05.02 बजे से

शनिवार 2025 वर्ष का 67 वा दिन
दिशाशूल पूर्व **ऋतु** शिशिर।
विक्रम संवत् 2081 **शक संवत्** 1946
मास फाल्गुन **पक्ष** शुक्ल
तिथि नवमी 08.17 बजे को समाप्त।
नक्षत्र आर्द्रा 23.29 बजे को समाप्त।
योग आयुष्मान 16.24 बजे को समाप्त।
करण कौलव 08.17 बजे तदनन्तर तैतिल 19.58 बजे को समाप्त।
चन्द्रायु 08.0 घण्टे
रवि क्रान्ति दक्षिण 04° 52'
सूर्य उत्तरायन
कलि अहर्गण 1872277
जूलियन दिन 2460742.5
कलियुग संवत् 5125
कल्पारंभ संवत् 1972949123
सृष्टि ग्रहारंभ संवत् 1955885123
वीरनिर्वाण संवत् 2551
हिजरी सन् 1446
महीना रमजान
तारीख 07
विशेष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।

दिन का चौघड़िया				रात का चौघड़िया			
काल	05.55	से	07.23 बजे तक	लाभ	05.37	से	07.10 बजे तक
शुभ	07.23	से	08.51 बजे तक	उद्वेग	07.10	से	08.42 बजे तक
रोग	08.51	से	10.19 बजे तक	शुभ	08.42	से	10.14 बजे तक
उद्वेग	10.19	से	11.46 बजे तक	अमृत	10.14	से	11.47 बजे तक
चर	11.46	से	01.14 बजे तक	चर	11.47	से	01.19 बजे तक
लाभ	01.14	से	02.42 बजे तक	रोग	01.19	से	02.51 बजे तक
अमृत	02.42	से	04.10 बजे तक	काल	02.51	से	04.23 बजे तक
काल	04.10	से	05.37 बजे तक	लाभ	04.23	से	05.56 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अत: आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। ■ Jagrutidaur.com, Bangalore

शब्द पहेली - 8425

1		■	2	■	3	■	4	5
	■	6		■	7	8	■	
9	10		■	11	■	12	13	
■		■	14		15	■		■
16				■	17			
■		■	18	19		■		■
20		21	■		■	22		23
	■	24	25	■	26		■	
27		■		■		■	28	

बाएँ से दाएँ

1. निशा, रात (उर्दू-2)
4. ताला (अंग्रेजी-2)
6. दुलारा, लाडला-2
7. बढ़ावा, समर्थन-2
9. निवास, घर, नीड़-3
12. कमी-3
14. पनाह, आश्रय-3
16. अंगूठे से तीसरी अंगुली, सावित्री-4
17. सज्जनता, सभ्यता-4
18. गिरवी रखी वस्तु-3
20. एक राशि-3
22. दबाव (अंग्रेजी-3)
24. कुल, मुनाफा-2
26. उम्मीद, आशा-2
27. मादा का विलोम-2
28. आगमन-2

ऊपर से नीचे

1. मदिरा, मय-3
2. ऐश्वर्या व अक्षय खन्ना की फिल्म-2
3. सम्मान, प्रसिद्धि-2
5. डोली उठाने वाले-3
6. वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीम के कप्तान-2
8. अधिकार-2
10. सेनापति, कप्तान-2,3
11. पति की मां-2
13. आत्मबलिदानी -5
14. कद काठी-3
15. रसद, किराणा-3
19. प्रत्येक-2
20. मैला, अस्वच्छ-3
21. मिट्टी, धूल-2
22. छापाखाना-2
23. जिव्हा, जीभ-3
25. सम्मान-2
26. फलों का राजा-2

शब्द पहेली -8424 का हल

■	ल	गा	म	■	प	ता	का	■
द	क्ष	■	ही	■	ह	■	ल	ता
रो	■	■	न	का	र	ना	■	क
गा	य	ब	■	न	■	ला	न	त
■	■	ल	ब	■	रा	य	■	■
आ	स	रा	■	ना	■	क	या	स
ई	■	म	हा	व	र	■	■	ह
ना	क	■	जि	■	सी	■	रा	ज
■	ल	की	र	■	ला	ग	त	■

■ Jagrutidaur.com, Bangalore

शादी से पूर्व परामर्श के लिए 'तेरे मेरे सपने' सेंटर खोलेगा राष्ट्रीय महिला आयोग।

Page-03_Layout 1 3/8/2025 2:22 AM Page 1

लखनऊ में बड़े इमामबाड़े की आसिफी मस्जिद के बाहर वक़्फ बिल के विरोध में शिया समुदाय ने जुमे की नमाज के बाद कल्बे जवाद के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया।

नमामि गंगे प्रोजेक्ट की सफलता को वैश्विक स्तर पर मिल रही है मान्यता : केंद्र

नई दिल्ली, (हि.स.)। केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर उठाए गए सवाल पर कहा कि गंगा के कायाकल्प में इस प्रोजेक्ट की सफलता को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। दिसंबर 2022 में पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक ने इसे शीर्ष 10 विश्व बहाली प्रमुख पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय जल संघ ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को जलवायु स्मार्ट उपयोगिता की उपाधि से सम्मानित किया, जिससे स्थायी जल प्रबंधन के लिए कार्यक्रम की प्रतिबद्धता और मजबूत हुई।

खरगे ने एक्स पोस्ट में कहा था कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए आवंटित फंड का 55 प्रतिशत भी खर्च नहीं किया गया। इस पर जलशक्ति मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि 2014 में शुरू किया गया नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा नदी के स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी और समग्र पहलों में से एक है। इसका बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदूषण निवारण, पारिस्थितिकी बहाली, क्षमता निर्माण और सामुदायिक सहभागिता को एकीकृत करता है, जिसमें नदी की पर्यावरणीय अखंडता और उस पर निर्भर लाखों लोगों की आजीविका दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

बयान में कहा गया है कि वर्ष 2014-15 से 2023-24 की अवधि के लिए 20,424.82 करोड़ रुपये के उपलब्ध संसाधनों के मुकाबले एनएमसीजी ने 16,648.49 करोड़ रुपये वितरित किए हैं, जो बजटीय प्रावधानों का 82 प्रतिशत है। यह ध्यान देने योग्य है कि कार्यक्रम के 42,500 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को तत्काल व्यय लक्ष्य (नकद व्यय) के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि यह एक स्वीकृत 17 वर्ष के जीवन चक्र के साथ प्रदूषण निवारण अवसंरचना के लिए वर्तमान व्यय और भविष्य की प्रतिबद्धताएं (वार्षिकी भुगतान / संचालन और रखरखाव व्यय) शामिल हैं। निर्मित एसटीपी के जिम्मेदार संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए हाइब्रिड वार्षिकी मॉडल को एक अभिनव दृष्टिकोण के रूप में अपनाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय का संचालन और रखरखाव चरण के 15 वर्षों में विस्तार हुआ है।

मंत्रालय ने बताया कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट ने प्रदूषण निवारण में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे 3,446 एमएलडी सीवेज उपचार क्षमता सृजित हुई है, जो 2014 से पहले की क्षमता से 30 गुना अधिक है। एनएमसीजी ने 7-8 वर्षों के भीतर 127 परियोजनाएं और 152 सीवेज उपचार संयंत्र पूरे किए हैं, जो गंगा नदी के प्राचीन गौरव को बहाल करने में उल्लेखनीय प्रगति दर्शाता है।

गुजरात से संगठन वर्ष की शुरूआत, चुनाव में उतरेंगे मजबूत प्लान के साथ : राहुल गांधी

अहमदाबाद, (हि.स.)। अपने दो दिवसीय दौरे पर गुजरात आए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कार्यकर्ताओं-नेताओं के साथ ताबड़तोड़ बैठक की। पार्टी के बड़े नेताओं के साथ ही उन्होंने तहसील-नगरपालिका प्रमुखों के साथ सीधा संवाद किया। गुजरात से संगठन वर्ष का ऐलान करते हुए उन्होंने गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को शिकस्त देने के लिए मजबूत प्लान के साथ मैदान में उतरने का कार्यकर्ताओं का आह्वान किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का शुक्रवार को गुजरात की धरती पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की ओर से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें एआईसीसी के संगठन प्रभारी महामंत्री केसी वेणुगोपाल, गुजरात के संगठन प्रभारी मुकुल वासनिक, गुजरात प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल, गुजरात विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमित चावडा समेत एआईसीसी के सचिव मौजूद रहे।

अहमदाबाद के राजीव गांधी भवन में प्रथम दिवस महत्व की बैठकों का दौर चला। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष दोशी के अनुसार सबसे पहले पार्टी के पूर्व प्रमुखों, पूर्व नेता प्रतिपक्ष के साथ जिला-शहर के प्रमुखों, तहसील-नगर के प्रमुख के साथ राज्य की प्रमुख समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा कांग्रेस के संगठन, राज्य में कांग्रेस की स्थिति मुद्दों पर मंथन किया गया। इस दौरान राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं से राज्य के नागरिकों के लिए न्याय, उनके हक और अधिकार को लेकर राज्य में रचनात्मक-आंदोलानात्मक कार्यक्रमों के आयोजन पर बल दिया। राहुल गांधी ने संगठन में व्यापक बदलाव के साथ ही पदाधिकारियों की जवाबदारी के साथ जवाबदेही पर भी जोर दिया। पार्टी राज्य में बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा, किसानों की समस्या आदि मुद्दों पर रणनीति बनाकर आंदोलन करेगी। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर राजनीतिक मामलों की समिति के सभी सदस्यों ने राजीव गांधी भवन में चर्चा की। सुझावों के साथ नए कार्यक्रमों के माध्यम से गुजरात के नागरिकों की आवाज को मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। जिला अध्यक्षों के साथ संवाद में बूथ तक संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। उचित रणनीति के माध्यम से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां को लेकर कार्यकर्ताओं को कमर कसने को कहा गया। पार्टी गुजरात में भाजपा को हराने के लिए एक मजबूत योजना के तहत काम करेगी। राहुल गांधी के साथ संवाद कार्यक्रम में 400 से अधिक तहसील-नगर पालिका के प्रमुख उपस्थित रहे। बैठक में राहुल गांधी के साथ स्थानीय नेतृत्व के साथ कांग्रेस पार्टी की सभी अच्छे-बुरे पासा को लेकर खुले मन से संवाद किया गया। एआईसीसी के संगठन प्रभारी एवं महासचिव केसी वेणुगोपालजी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संगठन वर्ष की शुरूआत गुजरात से की गयी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के गुजरात दौरे के दौरान हुई बैठकें कांग्रेस संगठन की आंतरिक बैठकें थीं, जिसमें हमारा पूरा ध्यान संगठन को मजबूत करने पर था, जिसके लिए राज्य, जिला और तहसील स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कैसे बदलाव किया जाए, इस पर सुझाव मांगे गए, चर्चा की गई। संगठन का फोकस सिर्फ गुजरात पर नहीं बल्कि पूरे भारत पर है। 8-9 अप्रैल को एआईसीसी के होने वाले अधिवेशन में एआईसीसी गुजरात कांग्रेस को रोडमैप तैयार कर सौंपेगा। हर नेता की जिम्मेदारी और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।

बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी : भारत

नई दिल्ली, (हि.स.)। भारत ने दोहराया है कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय और अन्य अल्पसंख्यकों की जान-माल की सुरक्षा वहां की अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है। पड़ोसी देश की जिम्मेदारी है कि वह अल्पसंख्यकों के जानमाल और धार्मिक संस्थाओं की सुरक्षा करे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पिछले वर्ष 5 अगस्त से बांग्लादेश में 2374 घटनाएं हुई हैं, जिनमें से पुलिस ने केवल 1254 की जांच की है। पुलिस जांच में 1254 घटनाओं में से 98 प्रतिशत को राजनीतिक प्रकृति का बताया गया है।

पटना। रमजान के पवित्र महीने के पहले जुमे की नमाज अदा करते लोग।

सेना के टी-72 टैंक 1000 एचपी इंजन से लैस किये जाएंगे, रूस से 248 मिलियन डॉलर का करार

नई दिल्ली, (हि.स.)। युद्धक टैंक टी-72 को अब 1000 हॉर्स पावर के इंजन से लैस किये जाने की तैयारी है, जिससे भारतीय सेना की युद्धक गतिशीलता और आक्रामक क्षमता बढ़ेगी। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को रूसी कंपनी रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के साथ 248 मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं इस सौदे में ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के तहत इंजनों को जोड़ने और बाद में चेन्नई के अवाडी स्थित आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (हैवी व्हीकल फैक्टरी) को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी शामिल है। रूस में निर्मित टी-72 भारतीय सेना के बेड़े का मुख्य टैंक है, जो अभी 780 हॉर्स पावर इंजन से संचालित है। भारत के पास टी-72 टैंक के कुल तीन वेरिएंट हैं। टी-72 टैंकों के मौजूदा बेड़े को अब 1000 एचपी इंजन से लैस किया जाएगा, जिससे भारतीय सेना की युद्धक गतिशीलता और आक्रामक क्षमता बढ़ेगी। इस टैंकको 1960 के दशक में सोवियत रूस ने विकसित और निर्मित करके रूसी सेना ने तमाम मोर्चों पर इसका इस्तेमाल शुरू किया। चीन के साथ 1962 में लड़ाई के बाद भारतीय सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने की योजना बनी। इसी क्रम में 1970 के आसपास भारत ने रूस से टी-72 टैंक खरीदा। यह यूरोप से बाहर भारत का पहला टैंक सौदा था और तबसे यह भारतीय सेना का भरोसेमंद साथी है।

चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में गतिरोध शुरू होने के बाद इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर तैनात किया गया है। इसी तैनाती के दौरान लद्दाख में एक ड्रिल के दौरान भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। यह सैनिक टी-72 टैंक पर सवार होकर श्योक नदी में अभ्यास कर रहे थे। इसी दौरान अचानक पानी का तेज बहाव आने से टैंक फंस गया और बाहर नहीं निकल पाया। टी-72 टैंक 41 हजार किलोग्राम (41 टन) वजनी है, जिसमें कुल 3 क्रू मेंबर्स के बैठने की जगह है। इस टैंक की ऊंचाई 2190 एमएम और चौड़ाई 3460 एमएम है। यह 60 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकता है, लेकिन कच्चे और खराब रास्तों पर इसकी गति 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे होती है।

सुकमा में एक महिला सहित पांच नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा, (हि.स.)। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल संगठन में सक्रिय एक महिला सहित पांच नक्सलियों ने शुक्रवार को पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर किया। इनमें दो-दो लाख रुपये के दो इनामी नक्सली शामिल हैं। एसपी किरण चव्हाण ने इसकी पुष्टि की है।

एसपी किरण ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति एवं सुकमा पुलिस द्वारा चलाये जा रहे नियद नेल्ला नार योजना से प्रभावित होकर नक्सली संगठन में सक्रिय एकमहिला सहित पांच नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह सरकार की नीति और सुरक्षाबलों के प्रभाव और रणनीति का परिणाम है कि नक्सली समाज की मुख्यधारा में लौट रहे हैं।

उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पित नक्सलियों में 38 वर्षीय माड़वी नंदा (पेद्दाबोड़केल आरपीसी सीएनएम अध्यक्ष इनामी दो लाख) निवासी करंगढ़ सरपंचपारा करकनगुड़ा थाना चिंतलनार जिला सुकमा, मड़कम माड़ा (पेद्दाबोड़केल आरपीसी डीएकेएमएस अध्यक्ष इनामी दो लाख) निवासी करकनगुड़ा थाना चिंतालनार जिला सुकमा, 44 वर्षीय महिला कवासी पाले पति स्व. पोज्जा (ग्राम करकनगुड़ा केएमएस अध्यक्ष) निवासी करकनगुड़ा थाना चिंतलनार जिला सुकमा, 34 वर्षीय मड़कम दषरू(पेद्दाबोड़केल आरपीसी सीएनएम उपाध्यक्ष) निवासी भीमापुरम थाना चिंतलनार जिला सुकमा, 25 वर्षीय मड़कम नंदा (ग्राम करकनगुड़ा मिलिशिया सदस्य)निवासी करकनगुड़ सरपंचपारा थाना चिंतलनार जिला सुकमा के द्वारा नक्सल संगठन को छोड़कर समाज की मुख्यधारा मे जुड़ने के उद्देश्य से सात मार्च 2025 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला सुकमा में सुखविन्द्र सिंह सहायक कमाण्डेन्ट 223 वाहिनी सीआरपीएफ, सहिल छिकारा, सहायक कमाण्डेन्ट 203 कोबरा वाहिनी एवं निरीक्षक रोशन सिंह राजपूत, प्रभारी नक्सल सेल जिला सुकमा के समक्ष बिना हथियार के आत्मसमर्पण किया गया।

नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित कराने 223 वाहिनी सीआरपीएफ सूचना शाखा के विशेष भूमिका थी। सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति के प्रोत्साहन राशि व अन्य सुविधायें प्रदान किये जायेंगे।

कर्नाटक बजट पर भाजपा का वार, कहा- तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस

नई दिल्ली, (हि.स.)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को राज्य का बजट पेश किया। इस बजट में मुसलमानों का विशेष ध्यान रखा गया है। कर्नाटक के इस बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला करते हुए इसे मुस्लिम लीग का बजट बताया है।

शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में राष्ट्रीय सचिव अनिल एंटनी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 140 करोड़ भारतीयों को 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर सशक्त बनाने के लिए समर्पित हैं। हमारा विकास मंत्र है- सभी का सशक्तीकरण और किसी का तुष्टीकरण नहीं। हालांकि, कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय पर अपनी साख को नजरअंदाज करती दिख रही है और तेजी से मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के आधुनिक संस्करण में तब्दील होती जा रही है। हाल ही में कर्नाटक ने अपने नए आइकन औरंगजेब से प्रेरित बजट जारी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वक्फ संपत्तियों की मरम्मत, जीर्णोद्धार और मुस्लिम कब्रिस्तानों के बुनियादी ढांचे और संरक्षण के लिए 150 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृति की है। कांग्रेस संविधान के खिलाफ धर्म के आधार पर आरक्षण देने का काम कर रही है। हम धर्म के आधार पर समाज को बांटने वाली कांग्रेस सरकार की नीति का विरोध करते हैं। कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों को ही अल्पसंख्यक मानती है और अन्य वास्तव में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को नजरअंदाज करती है। मुसलमानों के पास पहले से ही शिक्षा और रोजगार में आरक्षण है, जो संविधान के खिलाफ है। अब उन्हें सरकारी ठेकों में 4 प्रतिशत आरक्षण देना तुष्टीकरण की राजनीति का चरम है। भाजपा इसका विरोध करती है।

पंचकूला में भारतीय वायु सेना का लड़ाकू विमान जगुआर क्रैश, पायलट सुरक्षित।

जेपी नड्डा ने किया एम्स बिलासपुर में पीईटी-सीटी और स्पेक्ट-सीटी स्कैन सुविधा का शुभारंभ

शिमला, (हि.स.)। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शुक्रवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर में पीईटी-सीटी और स्पेक्ट-सीटी स्कैन सुविधा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ने जा रहा है। यहां आधुनिक तकनीकों से युक्त जांच सुविधाओं की शुरूआत से मरीजों को सटीक और त्वरित इलाज उपलब्ध होगा।

नड्डा ने कहा कि एम्स बिलासपुर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टि और भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों का परिणाम है। जब यह संस्थान अस्तित्व में आया था तब यह सिर्फ एक ढांचा था लेकिन आज यह अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस एक प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान बन गया है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य के लिए यह संस्थान वरदान साबित होगा क्योंकि अब यहां के लोगों को बड़े इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

नड्डा ने एम्स परिसर में विश्राम सदन और क्षेत्रीय वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक लैब (वीआरडीएल) का भी शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि विश्राम सदन की सुविधा से दूर-दराज से आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को ठहरने की उचित व्यवस्था मिलेगी। वहीं क्षेत्रीय वायरोलॉजी डायग्नोस्टिक लैब से वायरस जनित बीमारियों की जांच और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा जिससे प्रदेश की स्वास्थ्य सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि अनुसंधान और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभाएगा। यहां आधुनिक तकनीक से लैस चिकित्सा सुविधाएं मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होंगी।

हमीरपुर के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एम्स बिलासपुर में नई जांच सुविधाओं के शुभारंभ को प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से प्रदेशवासियों को इलाज के लिए चंडीगढ़, दिल्ली या अन्य बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं और आने वाले समय में और भी अत्याधुनिक सुविधाएं एम्स बिलासपुर में जोड़ी जाएंगी।

इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि एम्स बिलासपुर भाजपा सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जब प्रदेश में भाजपा सरकार थी, तब एम्स को स्थापित करने के लिए हरसंभव प्रयास किए गए। आज यह संस्थान प्रदेश के लाखों लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा से जनहित को प्राथमिकता देती रही है। एम्स बिलासपुर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले से मरीज यहां इलाज के लिए आ रहे हैं और अब नई सुविधाओं के जुड़ने से मरीजों को और अधिक राहत मिलेगी।

कार्यक्रम के दौरान एम्स बिलासपुर के अधिकारियों और डॉक्टरों ने केंद्रीय मंत्री नड्डा को अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की।

सम्पादकीय

महिला दिवस पर भारतीय महिलाओं की चर्चा

आज महिला दिवस है, महिलाओं को सम्पूर्ण विश्व में उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों से अवगत कराने के लिए प्रतिवर्ष 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित भी किया जाता है। वैसे दुनिया के कई देशों में महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है। विश्व के अधिकांश देशों में खासकर मुस्लिम देशों में उन्हें आज भी अधिकांश सामाजिक अधिकारों से बंचित रखा जाता है। अफगानिस्तान में तो तालिबान शासन में कड़े पर्दे में रहने के साथ शिक्षा सेभीवंचित रखा जा रहा है।

लेकिन भारत में महिलाओं की स्थिति वैदिक काल से ही अत्यंत सम्मानजनक रही है। भारतीय संस्कृति के आदिग्रन्थ वेद की ऋचाओं की रचना में आठ महिलाओं का योगदान रहा है। गार्गी आपाला आदि ऋषिकाओं का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। रामायण कालीन सती अनुसुड्या, सीता उर्मिला मन्दोदरी आदि का नाम आज भी आदरणीय, और समाज के लिए आदर्श है। महाभारत की द्रोपदी, कुंती, आदि का देश की संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान श्रीकृष्ण की पटरानी रुक्मिणी के साथ राधारानी का नाम अत्यंत श्रद्धा के साथ लिया जाता है। राधा तो तो आज भी करोडों सनातनियों की आराध्य हैं।

पौराणिक काल के बाद आधुनिक एवं मध्यकाल में भी भारतीय नारियों का इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई के महान शासन और सम्पूर्ण देशमै मंदिरों के निर्माण, पुनर्निर्माण को कौन भुला सकता है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1857 ई०) की नायिका झांसी की रानी लक्ष्मी बाई के तलवार की धार को कौन भूल सकता है। अंग्रेजी शासन के विरुध्द चले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान श्रीमती ऐनी वेसेंट, श्री मती सरोजिनी नायडू श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित सुचेता कृपामानी आदि प्रथमपंक्ति की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रही हैं। देश की महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरागांधी की कूटनीति एवं शासन संचालन अद्वितीय मानी जाती है। उनके दृढ़ निश्चय कारण ही बांग्लादेश का निर्माण हुआ।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चल रही वर्तमान सरकार ने पिछले दस वर्षों में महिलाओं के कल्याण अनेक कदम उठाये गये। पिछले वर्ष संसद में पारित नारी सशक्तीकरण विधेयक के द्वारा महिला को संसद में सहित प्रदेशों की सभी विधायिकाकों में एक निहाई आरक्षण देने का फैसला किया है गया है। यह महिलाओं को मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय है। महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण के साथ कई प्रदेश सरकारों ने कई विभिन्न नामों से उन्हें प्रतिमाह धनराशि देना शुरू कर दिया है। दिल्ली में भाजपा की नई सरकार की मुखिया श्रीमती रेखा गुप्ता को बनाकर महिला सम्मान को नई दिशा प्रदान की गई है।

हिंदी के खिलाफ जहर उगलते स्टालिन

राष्ट्रभाषा हिंदी को लेकर दक्षिण भारत के राज्य हमेशा से ही विरोध करते आ रहे हैं। इन दक्षिणी राज्यों में हिंदी का विरोध करने वालों में तमिलनाडु सबसे प्रमुख राज्य है। इस राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं वह सब राष्ट्रभाषा हिंदी का विरोध करते हुए अपने राज्य की तमिल भाषा के सबसे बड़े हितेशी बने रहने का झंडा उठाएं रहे हैं। पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों की हिंदी के विरोध करने की परंपरा का निर्वाहन तमिलनाडु के मौजूदा मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी जारी रखा है। वह हमेशा किसी न किसी मौके पर राष्ट्रभाषा हिंदी का विरोध करते रहते हैं। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिंदी और संस्कृत भाषा को लेकर एक पत्र भी लिख भेजा है। स्टालिन ने अपने पत्र में लिखा है कि तमिलनाडु सरकार नई शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा नीति के विरुद्ध है। स्टालिन केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप भी लगा रहे हैं। हिंदी का विरोध करते हुए स्टालिन कहते हैं कि वह हिंदी के खिलाफ हैं और हर हालत में तमिल और उसकी संस्कृति की रक्षा करेंगे। स्टालिन ने कार्यकर्ताओं को जो पत्र भेजा है उसमें भी लिखते हैं कि हम हिंदी थोपे जाने का विरोध करते हैं और उनके लिए हिंदी एक मुखौटा है और उसके पीछे का चेहरा संस्कृत है। तमिलनाडु की द्रमुक सरकार केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तीन भाषा के फामूर्ले के जरिए हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है। स्टालिन अपने पत्र में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़े शातिराना तरीके से हिंदी भाषी राज्यों के लोगों को भी भडकाने का काम किया है। स्टालिन हिंदी भाषी राज्यों के लोगों को यह बतला रहे हैं कि हिंदी ने अन्य भारतीय भाषाओं को निगल लिया है। स्टालिन पत्र में लिखते हैं भोजपुरी, मैथिली, अवधि, बुंदेली, मगही, मालवी,गढ़वाली, ब्रज, कुमाऊनी, मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी,संथाली, अंगिका, खारिया, खोरठा, कुरमाली कुरूख एवं मुंडारी समेत कई क्षेत्रीय भाषाओं का स्टालिन उल्लेख करते हैं और लिखते हैं कि यह सभी क्षेत्रीय भाषाएं अपने अस्तित्व के लिए हांफ रही हैं। अखंड हिंदी पहचान की कोशिशें से प्राचीन भाषायें नष्ट हुई हैं। स्टालिन ने अपने पत्र में यह भी बतलाया है कि यूपी बिहार हार्टलेंड नहीं थे। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में बोली जाने वाली कई भाषाओं जैसे मैथिली, ब्रजभाषा बुंदेलखंडी और अवधि को हिंदी के प्रभुत्व ने नष्ट कर दिया है। वही स्टालिन यह भी आरोप लगा रहे हैं कि संस्कृत भाषा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है और कई राज्य सरकारें अपने राज्य में संस्कृत को लागू करने की कोशिश भी जारी रखे हैं। दक्षिण भारत के राज्य अपने राज्य की भाषा का संरक्षण और संवर्धन करें इसे लेकर किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती है। आज गुजरात सरकार गुजराती भाषा में महाराष्ट्र सरकार मराठी में और आंध्र प्रदेश की सरकार तेलुगु भाषा में सरकारी कामकाज करती आ रही हैं। इन सरकारों ने कभी भी अपने राज्यों में सरकारी कामकाज को हिंदी भाषा में करने के लिए दबाव ही नहीं बनाया है। इसलिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का यह आरोप बेबुनियाद नजर आ रहा है कि हिंदी भाषा क्षेत्रीय भाषाओं को निगल रही है। अब देखना है कि केंद्र सरकार हिंदी और त्रिभाषा नीति को लेकर हिंदी का विरोध करने वाले राज्यों के लिए किस प्रकार की रणनीति बनाती है।

आरएनआई नं. DELHIN/2009/28518 स्वामी, सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक रमाकांत पाण्डेय द्वारा दिव्य भारत प्रकाशन के लिए न-93 डी नारायण नगर दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफल इंफोटेक लि., प्रेस, सी-9 सेक्टर 3 नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : रमाकांत पाण्डेय, कार्यकारी सम्पादक : आलोक पाण्डेय, फोन : 7701825882, 7905152597, पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत समाचारों के चयन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी।
E-mail : newdibyabharat@gmail.com

बलात्कार और हिंसा पर कब टूटेगी समाज की चुप्पी

दुनियाभर में प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो सही मायनों में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने वाला एक वैश्विक दिवस है। यह दिन लैंगिक समानता में तेजी लाने के लिए कार्रवाई के आह्वान का भी प्रतीक है। हालांकि चिंता का विषय यही है कि जिस आधी दुनिया के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, उसी आधी दुनिया को जीवन के हर मोड़ पर भेदभाव या अपराधों का सामना करना पड़ता है। यदि इसे भारत के ही संदर्भ में देखें तो शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता हो, जब आधी दुनिया से जुड़े अपराधों के मामले देश के कोने-कोने से सामने न आते हों। होता सिर्फ यही है कि जब भी कोई बड़ा मामला सामने आता है तो हम सिर्फ पुलिस-प्रशासन को कोसने और संसद से लेकर सड़क तक कैंडल मार्च निकालने या अन्य किसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन करने की रस्म अदायगी करके शांत हो जाते हैं और पुनः तभी जागते हैं, जब ऐसा ही कोई बड़ा मामला पुनः सुर्खियां बनता है, अन्यथा ऐसी छोटी-मोटी घटनाएं तो आए दिन होती ही रहती हैं।

देश में कानूनों में सख्ती, महिला सुरक्षा के नाम पर बीते कुछ वर्षों में कई तरह के कदम उठाने और समाज में आधी दुनिया के आत्मसम्मान को लेकर बढ़ती संवेदनशीलता के बावजूद आखिर ऐसे क्या कारण हैं कि बलात्कार के मामले हों या छेड़छाड़ अथवा मयार्दा हनन या फिर अपहरण अथवा क्रूरता, आधी दुनिया के प्रति अपराधों का सिलसिला थम नहीं रहा है? इसका एक बड़ा कारण तो यही है कि कड़े कानूनों के बावजूद असामाजिक तत्वों पर वो कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके वो हकदार हैं और इसके अभाव में हम ऐसे अपराधियों के मन में भय पैदा करने में असफल हो रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा कि महज कानून कड़े कर देने से ही महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध थमने से रहे, जब तक उनका ईमानदारीपूर्वक कड़ाई से पालन न किया जाए। ऐसे मामलों में पुलिस-प्रशासन की भूमिका भी अनेक अवसरों पर संदिग्ध रहती है। पुलिस किस प्रकार ऐसे अनेक मामलों में पीड़िताओं को ही परेशान करके उनके जले पर नमक छिड़कने का कार्य करती है, ऐसे उदाहरण अक्सर सामने आते रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों के मद्देनजर अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का भय कैसे उत्पन्न होगा और कैसे महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों में कमी की उम्मीद की जाए? जरूरत इस बात की महसूस की जाने लगी है कि पुलिस को लैंगिक दृष्टि से संवेदनशील बनाया जाए ताकि पुलिस पीड़ित पक्ष को पर्याप्त संबल प्रदान करे और पीडिताएं अपराधियों के खिलाफ खुलकर खड़ा होने की हिम्मत जुटा सकें, साथ ही जांच एजेंसियों और न्यायिक तंत्र से भी ऐसे मामलों में तत्परता से कार्रवाई की अपेक्षा की जानी चाहिए। ऐसी घटनाओं पर अंकुश के लिए समय की मांग यही है कि सरकारें मशीनरी को चुस्त-दुरूस्त बनाने के साथ-साथ प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करें कि यदि उनके क्षेत्र में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों के मामलों में कानून का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हुआ तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए।

सामने आती दिनदहाड़े छेड़छाड़, अपहरण, बलात्कार या सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटनाएं सभ्य समाज के माथे पर बदनुमा दाग के समान हैं और यह कहना असंगत नहीं होगा कि महज कड़े कानून बना देने से ही महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगने वाला। आए दिन देशभर में हो रही इस तरह की घटनाएं हमारी सभ्यता की पोल खोलने के लिए पर्याप्त हैं। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि बलात्कार और छेड़छाड़ के जो मामले सामने आ रहे हैं, उनमें बहुत से ऐसे भी होते हैं, जिनमें पीड़िता के परिजन, निकट संबंधी या परिचित ही आरोपी होते हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों में तो यहां तक कहा जा चुका है कि करीब 97 फीसदी मामलों में महिलाएं अपनों की ही शिकार होती हैं और यह समस्या सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है बल्कि महिला अपराधों के मामले में पूरी दुनिया की यही तस्वीर है। जहां देश में हर 53 मिनट में एक महिला यौन शोषण की शिकार होती है और हर 28 मिनट में अपहरण का मामला सामने आता है, वहीं संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में प्रत्येक तीन में से एक महिला का कभी न कभी शारीरिक शोषण होता है। दुनिया में करीब 71 फीसदी महिलाएं शारीरिक मानसिक प्रताड़ना अथवा यौन शोषण व हिंसा की शिकार होती हैं, दक्षिण अफ्रीका में हर छह घंटे में एक महिला को उसके साथी द्वारा ही मौत के घाट उतार दिया जाता है और अमेरिका में भी इसी प्रकार कई महिलाएं हर साल अपने ही परिचितों द्वारा मार दी जाती हैं।

जहां तक पीड़िताओं को न्याय दिलाने की बात है तो इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग काफी समय से उठती रही है किन्तु हमारा सिस्टम कछुआ चाल से रेंग रहा है। ऐसे मामलों में कठोरता बरतने के साथ-साथ त्वरित न्याय प्रणाली की भी सख्त जरूरत है ताकि महिला अपराधों पर अंकुश लग सके। आज अगर समाज में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के बावजूद महिलाओं के प्रति अपराध और संवेदनहीनता के मामले बढ़ रहे हैं तो हमें यह जानने के प्रयास करने होंगे कि कमी हमारी शिक्षा प्रणाली में है या कारण कुछ और हैं। ऐसे कृत्यों में लिप्त रहने वाले लोगों की कुंठित मानसिकता के कारणों की पड़ताल करना भी बहुत जरूरी है, साथ ही सामाजिक मूल्यों का विकास करने के लिए विद्यालयों में नैतिक शिक्षा को लागू करना और छात्रों को अच्छा साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करना समय की मांग है ताकि युवाओं की नकारात्मक सोच को परिवर्तित करने में मदद मिल सके, जिससे स्थिति में सुधार की उम्मीद की जा सके।

–योगेश कुमार गोयल
(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

क्लारा जेटकिन महिला अधिकारों की प्रखर नेता

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस महिलाओं के अधिकारों, उनकी समानता, स्वतंत्रता और उनकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृति और राजनीतिक उपलब्धियों को पहचानने के लिये जाना जाता है। आज इसका इतिहास कोई सवा सौ वर्ष पुराना हो चुका है। विश्व के लगभग सभी देशों में यह खास दिन लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने साथ महिलाओं सहित पुरुषों के सहयोग और उनमें संवेदनशीलता जगाने का माध्यम भी बनता है। इस दिवस की यही उपलब्धि भी है कि महिलाओं के साथ पुरुष भी पितृसत्ता को पहचानते हुये उसके दुष्परिणामों के प्रति सजग होकर महिलाओं के साथ एक सुंदर समाज का निर्माण करें।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के इन उद्देश्यों के परे यह जानने में हम सबकी उत्सुकता इस बात में जरूर होनी चाहिये कि इस ऐतिहासिक दिवस को मूर्त रूप देने में किन लोगों का सार्थक प्रयास रहा और उनके किन प्रयासों से महिलाओं को आज पुरुषों के समान अधिकारों की बात की जा रही है। उनमें से एक प्रमुख नाम क्लारा जेटकिन (1857-1933) का आता है जिनके प्रयासों से यह दिवस आज हम सब मना पा रहे हैं। वे एक जर्मन समाजवादी, नारीवादी और राजनीतिक कार्यकर्ता थीं, जिन्होंने महिला अधिकारों, श्रमिक आंदोलन और समाजवाद के लिए जीवनभर संघर्ष किया। क्लारा जेटकिन का जन्म 1857 में जर्मनी में हुआ था। उनकी मां भी महिला अधिकारों के लिये संघर्षरत थीं। ऐसे में वे बचपन से ही इस तरह के आंदोलनों के प्रमुख नेताओं के संपर्क में आने लगीं। वे स्कूली दिनों में ही रूसी क्रांतिकारी आंदोलन से परिचित हो चुकी थीं और जर्मन मजदूर आंदोलन से सहानुभूति रखती थीं। बाद में रूसी क्रांतिकारी ओसिप जेटकिन के संपर्क में आईं और उनके साथ काम भी किया। बाद में वे उनके जीनवसाथी भी बने। 1881 में क्लारा जेटकिन अपने पति के साथ पेरिस चली गईं, जब उन्हें जर्मनी से देश निकाला दे दिया गया था। यह वह समय था जब जर्मन मजदूर आंदोलन और उनकी पार्टी जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को कई तरह के प्रतिबंध झेलने पड़े। 12 साल बाद 1890 में उन्हें इस तरह के प्रतिबंध से निजात मिलीं।

इस दौरान पेरिस में रहते हुये क्लारा सक्रिय रहीं अपने लेखों और भाषणों से महिला अधिकारों को आवाज उठाती रही। इसका परिणाम यह रहा कि उन्हें 1889 में महिलाओं से जुड़े सवालों पर दूसरी इंटरनेशनल कांग्रेस को संबोधित करने के लिये आमंत्रित किया गया। यहां वे एक सक्रिय महिला अधिकारों की प्रवक्ता बन कर उभरीं। 1891 में जर्मनी लौटने के साथ उन्होंने महिला अधिकारों की वकालत करने के लिये डाइ ग्लीचहाइट नामक पत्रिका की स्थापना की और उसका आगे 25 सालों तक संपादन कार्य भी किया। जर्मन पत्रिका डाइ ग्लीचहाइट का अर्थ समानता है। इसके उप शीर्षक में महिला मजदूरों के हितों के लिये लिखा जाता था।

1890 के दशक से लेकर प्रथम विश्वयुद्ध के शुरू होने तक जेटकिन ने जर्मन समाजवादी महिला आंदोलन को सफलतापूर्वक खड़ा करने के लिए अपनी ऊर्जा समर्पित की। 1907 तक समाजवादी महिला आंदोलन में 75,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल हो चुकी थीं। यह डाइ ग्लीचहाइट के सदस्यता अभियान से पता चलता है। हजारों महिलाओं को ट्रेड यूनियनों, शिक्षा समितियों में संगठित किया गया और 1908 के बाद जब महिला संघ के विरुद्ध कानून निरस्त कर दिया गया, तो एसपीडी में भी शामिल हो गईं। 1914 तक जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एसपीडी की 174,474 महिला सदस्य थीं। इसी बात से उनके कुशल सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता होने का सबूत मिलता है। 1910 का सोशलिस्ट इंटरनेशनल महिला सम्मेलन महिलाओं के अधिकारों और समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ था। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का प्रस्ताव 1910 में कोपेनहेगन (डेनमार्क) में आयोजित इसी सम्मेलन में रखा गया था। क्लारा ने सुझाव दिया कि हर साल एक दिन अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, ताकि दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों, समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रस्ताव को 17 देशों की 100 से अधिक महिलाओं ने समर्थन दिया। क्लारा जेटकिन के प्रस्ताव के एक साल बाद, 1911 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। यह 19 मार्च 1911 को ऑस्ट्रिया, जर्मनी, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड में मनाया गया। लाखों महिलाओं और पुरुषों ने रैलियों, प्रदर्शनों और सभाओं के माध्यम से महिला अधिकारों की मांग की। इसके बाद 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक मान्यता दी और इसे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया।

–प्रतिभा कुशवाहा
(लेखिका, हिन्दुस्थान समाचार की पत्रिका युगवार्ता से संबद्ध हैं।)

भारत की नारी

संसार की सभी मानवीय सभ्यताओं में स्त्री के संदर्भ में चर्चा सदैव से व्यापक रही हैं। भारतीय परिपेक्ष्य में स्त्री को सदा ही आदर के साथ पूजनीय माना जाता रहा है। यहां के संस्कारों में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' जैसे श्लोक प्रकट होते हैं जैसा की अनेकों ऐतिहासिक प्रमाणों ने यह सिद्ध किया है की लगभग 1000-1500 ईसा पूर्व. से ही भारतीय संस्कृति अस्तित्व में है जिसे इतिहास की दृष्टि से वैदिक काल भी कहा जाता है। इस वैदिक काल में भी ऋग्वेद को लिखने में ऋषियों के साथ-साथ 27 ऋषिकाओं का भी उल्लेख किया जाता है जिसमें विश्र्ववारा, शाश्वती, इंद्राणी, अदिति, सूर्या आदि ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। यह ऋषिकाएं अपने ज्ञान के माध्यम से ही ऋषिका पद को प्राप्त होती थी तथा उस वैदिक काल में जहां अभी अन्य सभ्यताएं जन्म ही ले रही थी वहीं भारतीय संस्कृति में स्त्रियां समाज में बराबर का योगदान दे रही थी। भारतीय समाज शुरू से ही स्त्रियों को प्रतीकात्मक रूप से शक्ति, समृद्धि व ज्ञान का केंद्र मानता आया है यहां पर आदिकाल से ही त्रिदेवियों (काली, लक्ष्मी, सरस्वती) की एक व्यापक अवधारणा रही है। जो केवल एक रूप मात्र ही नहीं अपितु सामाजिक सत्ता के तीन प्रमुख बिंदु बल, बुद्धि, अर्थ को प्रकाशित करती हैं।

यानी समाज में कौन कितना शक्तिशाली है यह निश्चित करने का काम एक स्त्री द्वारा ही किया जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद् में महाराजा जनक की सभा का वर्णन आता है जहां वह पूरे विश्व के विद्वानों को आमंत्रित करके शास्त्रार्थ आयोजित करवाया करते थे। वहां पर भी हमें याज्ञवल्क्य जी और गार्गी जी का विश्व प्रसिद्ध संवाद देखने को मिलता है जिसमें साध्वी गार्गी पूरी सभा के सामने अपनी विद्वत्ता का परिचय देते हुए सभी को अपनी ज्ञानमय वाणी से परास्त कर देती हैं। यही नहीं आदि गुरु शंकराचार्य जी और मंडल मिश्र के शास्त्रार्थ की मध्यस्थता भी उभय भारती जो मंडल मिश्र की धर्मपत्नी तथा एक स्त्री थी उनके द्वारा ही करी गई थी। अर्थात भारतीय इतिहास में स्त्रियां शुरू से ही एक महत्वपूर्ण निणार्याक के रूप में कार्य करती आई हैं। हम सभी जानते हैं कि संसार की उत्पत्ति करने में स्त्री का कितना बड़ा योगदान होता है। एक स्त्री असंख्य पीड़ाओं को सहकर तथा अनेकों कष्टों को सहकर संसार के चक्र को चलाए रखना का कार्य करती हैं। यदि स्त्री चाहे तो वह संसार के चक्र को तोड़कर विनाश करने में भी समर्थ है, परंतु उसकी संरचना ही इस प्रकार है कि वह विनाश की ना सोचकर सदा सृजन के बारे में ही सोचती है और संसार के क्रम को आगे बढ़ाती है। इसलिए भारतीय संस्कृति में स्त्री को एक महाशक्ति के रूप में देखा जाता है जो संपूर्ण धरा का संचालन करती है।

शुरू में जब स्त्री शब्द का उल्लेख होता है तो सर्वप्रथम ध्यान में माता के स्वरूप का ही विचार आता है। माता यानी जो पालन करती हो, जो पोषित करती हो, जो रक्षा करती हो तथा जो विकसित करती हो। और भारत में यह कार्य करने वाले प्रत्येक तत्व को माता का ही रूप माना जाता है जिसमें धरती माता, भारत माता, प्रकुति माता, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा सिंधु, कावेरी जैसी नदियां और प्रत्येक वह अवयव जो करुणा का भाव रखता हो उन सबको माता का ही दर्जा दिया जाता है। भारत में स्त्री केवल मां के रूप में ही नहीं अपितु बहन, बेटी, पत्नी, बहू आदि रूपों में भी प्रकट होती है। भारत में ऐसे रिश्तों की एक विशाल परंपरा रही है जिसमें एक ही स्त्री एक साथ अनेकों रूपों में दिखाई पड़ती है और हर एक रूप में उसका एक अलग किरदार देखने को मिलता है यह रिश्तो का अनोखा संगम केवल भारतीय संस्कृति में ही देखा जा सकता है। जिसमें स्त्री, बहन के रूप में भाई का सहयोग करती है, मां के रूप में संतान का ध्यान करती है, पत्नी के रूप में पुरुष का हर घड़ी साथ निभाती है तथा बेटी के रूप में समाज में सम्मान बढ़ाती है। यह महिला के अलग-अलग रूप सनातन संस्कृति को सुदृढ़ बनाने का कार्य करते हैं तथा यही नहीं भारतीय परिधान में स्त्रियों के और भी ऐसे अनेक रूप देखने को मिलते हैं जो इस परंपरा की एक अलग पहचान बनते हैं। यहां पर दादी, नानी, बुआ, मौसी सखी-सहेली का भी एक अलग सिद्धांत है जो मां, बहन, बेटी का ही एक उन्नत प्रकार है। आज का समय नए-नए आविष्कारों का है तथा तकनीकी जगत में एक खोज के बाद उसकी महत खोज का प्रयास किया जाता है परंतु भारत में तो ऐसी आधुनिक खोज का प्रचलन शुरू से ही रहा है। हम जो यह दादी, नानी, बुआ, मौसी का रूप देखते हैं यह मां-बहन का ही एक उन्नत प्रकार है जो तकनीकी और व्यावहारिक दृष्टि से भी प्रमाणित है। तकनीकी भाषा में हम इन रूपों को अपडेटेड सॉफ्टवेयर की संज्ञा दे सकते हैं। जो एक रूप से विकसित होकर उसी कार्य को करने के लिए नए रूप को धारण करते हैं तथा स्त्री का यह रूप स्त्री के स्त्रीत्व को अत्यंत प्रभावित रूप से परिभाषित करता है। आजकल एकल परिवार के चलते स्त्री के यह रूप कम ही देखने को मिलते हैं परंतु भारत की मातृशक्ति इन सभी रूपों को मिलाने के पश्चात ही अपने पूर्ण आकार में आती है। यह विभिन्न रूपों में वगीर्कृत स्त्री के तमाम रूप ही भारत के स्त्री विमर्श को परिभाषित करने का कार्य करते हैं क्योंकि यहां स्त्री केवल चयनित कार्यों को नहीं अपितु असंख्य कार्यो, व्यवहारों, विचारों, संस्कारों और सुधारो का संचालन करती है। इन सभी आयामों को समाज में लाने का कार्य स्त्री ही करती है स्त्री ही एक समृद्ध व सुव्यवस्थित समाज को स्थापित कर सकती है तथा स्त्री के पास ही वह ताकत है जो समाज में परिवर्तन ला सकती है। और भारतीय इतिहास में तो ऐसी अनेकों स्त्रियां हुई हैं जो संपूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा बनी है। हमारे यहां रानी अहिल्याबाई, सावित्रीबाई, लक्ष्मीबाई, ज्योतिबा फुले, आंडाल, मीराबाई, बीकाजी कामा जैसे असंख्य उदाहरण है जिन्होंने अपने परिश्रम व दृढ़ संकल्प से भारतीय स्त्रियों के स्त्रीत्व की संपूर्ण विश्व के समक्ष परिभाषा प्रस्तुत करी है तथा भारतीय स्त्रियों में स्व का बोध जागृत कराया है। ऐसी महान स्त्री परंपरा व स्त्रीत्व के सिद्धांत को हम बारंबार प्रणाम करते हैं जो सदा जरूरत पड़ने पर हर रूप में चट्टान की भांति हर स्थिति में मजबूती से खड़ी रहती हैं तथा एक उच्चतम सांस्कृतिक परंपरा का प्रवाह बनती है।

–हर्ष कुमार बघेल
हिंदू अध्ययन केंद्र,दिल्ली विश्वविद्यालय

डिजिटल क्रांति और आर्थिक उन्नति की नई मिसाल बना यूपी

- **योगी राज में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लेकर डिजिटल लेनदेन में यूपी ने रचा कीर्तिमान**
- **जीएसडीपी में दोगुने से अधिक की हुई वृद्धि, देश के सामने उत्तर प्रदेश पेश कर रहा प्रेरणादायक उदाहरण**
- **2017-18 में करीब 122 करोड़, जबकि 2024-25 में 1024.41 करोड़ का हुआ डिजिटल ट्रांजेक्शन**
- **1950-2017 तक 12.75 लाख करोड़ की जीएसडीपी 2024-25 में 27.51 लाख करोड़ की होने जा रही है**
- **नीति आयोग ने यूपी को दिया है 'फ्रंट रनर' का दर्जा**
- **आरबीआई के अनुसार 2024-25 में महाराष्ट्र के बाद देश में सर्वाधिक है यूपी की कर हिस्सेदारी**

उत्तर प्रदेश ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में डिजिटल क्रांति और आर्थिक प्रगति के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से लेकर डिजिटल लेनदेन और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में अभूतपूर्व वृद्धि तक, यूपी आज देश के सामने एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। नीति आयोग ने जहां यूपी को 'फ्रंट रनर' का दर्जा दिया है, वहीं भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में राज्य की कर हिस्सेदारी 11.6% रही, जो महाराष्ट्र के बाद देश में सर्वाधिक है। यह उपलब्धि निःसंदेह सीएम योगी के प्रयासों से यूपी को विकास के पथ पर अग्रणी राज्य बनाती है।

उत्तर प्रदेश ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में देश में नंबर एक स्थान हासिल किया है। 2017-18 में जहां राज्य में 122.84 करोड़ के डिजिटल लेनदेन दर्ज किए गए थे, वहीं 2024-25 में दिसंबर 2024 तक यह आंकड़ा 1024.41 करोड़ तक पहुंच गया। इसमें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का आधे से अधिक योगदान रहा। डिजिटल बैंकिंग की आसान पहुंच, गांवों तक इंटरनेट की उपलब्धता, वित्तीय जागरूकता और पर्याप्त उपकरणों ने इस क्रांति को यूपी में संभव बनाया। राज्य में 20,416 बैंक शाखाएं, 4,00,932 बैंक मित्र और बीसी सखी, 18,747 एटीएम और 4,40,095 बैंकिंग केंद्र इसकी मजबूत आधारभूत संरचना को दशार्ते हैं। डीबीटी के माध्यम से योगी सरकार ने 11 विभागों की 207 योजनाओं के तहत 9 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों के खातों में 1,11,637 करोड़ का भुगतान किया है। इसमें 113 केंद्रीय और 94 राज्य योजनाएं शामिल हैं। इस प्रणाली ने न केवल योजनाओं के पात्रता में पारदर्शिता बढ़ाई है, बल्कि 10 हजार करोड़ की बचत भी की है। यह प्रक्रिया न सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाती है, बल्कि जरूरतमंदों तक सीधे लाभ पहुंचाने में भी कारगर सिद्ध हुई है। यूपी इस मामले में डिजिटल क्रांति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बनकर उभरा है।

1950 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी महज 12.75 लाख करोड़ तक पहुंच सकी थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर जनता के भरोसे और 2017 से योगी सरकार की मेहनत से पिछले आठ वर्षों में यह आंकड़ा दोगुना से अधिक होकर 2024-25 में 27.51 लाख करोड़ तक पहुंचने जा रहा है। देश की जीडीपी में 9.2% हिस्सेदारी के साथ यूपी अब देश का दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक योगदानकर्ता बन गया है। 2023-24 में जहां देश की जीडीपी वृद्धि दर 9.6% रही, वहीं यूपी ने 11.6% की दर से आगे बढ़कर अपनी आर्थिक ताकत का परिचय दिया है। नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को राजकोषीय स्थिति के मामले में 'फ्रंट रनर' घोषित किया गया है। 2018-19 से 2022-23 के बीच राज्य के 'फिस्कल हेल्थ इंडेक्स' में 8.9 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। पूंजीगत व्यय में भी सुधार देखा गया है, जो कुल व्यय का 14.8% से बढ़कर 19.3% हो गया। यह अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के औसत से अधिक है। आरबीआई की 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार, यूपी की स्वयं के कर से प्राप्ति का अनुपात 10% रहा, जो राष्ट्रीय औसत 7.2% से कहीं अधिक है। यह राज्य की आर्थिक नीतियों की मजबूती को दशार्ता है।

–रमाकान्त पाण्डेय

Page-05_Layout 1 3/8/2025 3:24 AM Page 1

सांबा प्रशासन ने बड़े उत्साह के साथ मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।

सांबा प्रशासन ने बड़े उत्साह के साथ मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

दिव्य भारत संवाददाता

सांबा। जिला प्रशासन सांबा ने समाज कल्याण विभाग के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक जीवंत समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र में महिलाओं की उपलब्धियों और उद्यमिता को उजागर करने वाली गतिविधियों की एक प्रभावशाली श्रृंखला शामिल थी।

जेके एसएसबी की अध्यक्ष इंदु कंवल चिब ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई। सांबा के डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने इस सार्थक समारोह को आयोजित करने में प्रशासन का नेतृत्व किया। कार्यक्रम में संगीतकार सोनाली डोगरा द्वारा एक विशेष प्रस्तुति और कॉलेज के छात्रों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रदर्शन शामिल थे, जिसमें क्षेत्र की समृद्ध विरासत को दिखाया गया।

उपायुक्त श्रीनगर ने खाद्य सुरक्षा पर जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की

दिव्य भारत संवाददाता

श्रीनगर। जिले में लोगों को गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों की समीक्षा के लिए डीसी कार्यालय परिसर के मीटिंग हॉल में डिप्टी कमिश्नर (डीसी) श्रीनगर डॉ.बिलाल मोहि-उद-दीन भट की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा और स्वस्थ आहार पर जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। शुरूआत में, डीसी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के संबंध में खाद्य सुरक्षा विभाग के कामकाज और उपलब्धियों की व्यापक समीक्षा की। बैठक में जिले में खाद्य व्यापार संचालकों द्वारा अपनाए जा रहे खाद्य सुरक्षा मानकों और स्वच्छता से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

इस अवसर पर, उपायुक्त, जो डीएलएसी के अध्यक्ष भी हैं, को श्रीनगर जिले में खाद्य सुरक्षा उपायों की वर्तमान स्थिति और जनता के लिए सुरक्षित और स्वस्थ भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा किए गए विभिन्न सक्रिय उपायों के बारे में अवगत कराया गया। डॉ. बिलाल ने जिले भर में बाजार की जांच तेज करने पर जोर दिया और मानव जीवन की सुरक्षा के लिए अध्ययन के लिए वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को अपनाकर और प्रशासन के साथ निष्कर्षों को साझा करके खाद्य नमूनों की मात्रा बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उल्लंघन में शामिल एफबीओ के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। डीसी ने श्रीनगर जिले में शिकायत निवारण तंत्र को और मजबूत करने पर भी जोर दिया, ताकि उपभोक्ताओं की वास्तविक शिकायतों को प्रोत्साहित किया जा सके और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ समय पर कार्रवाई की जा सके, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण और चिंतित क्षेत्र को नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा, डीसी ने अधिकारियों को सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार बनाए रखने के महत्व पर जनता को शिक्षित करने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करते हुए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि खाद्य नियामक कानूनों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से लगभग 1400 निरीक्षण किए गए, जबकि इसी अवधि के दौरान 1967 कानूनी और निगरानी नमूने उठाए गए। इसके अलावा, सक्षम न्यायालयों के समक्ष विभिन्न मामले दायर किए गए हैं और उल्लंघनकर्ताओं पर 177000 रुपये का जुमार्ना लगाया गया है।

स्थायी विकास के लिए हमें अधिक रचनात्मक नेताओं की आवश्यकता है : राज्यपाल

दिव्य भारत संवाददाता

- **हमें प्रौद्योगिकी और कला के बीच एक अच्छा संतुलन बनाने की आवश्यकता है**
- **समाज का आर्थिक विकास कला और संस्कृति द्वारा संचालित होता है**
- **कला एक प्रबुद्ध समाज के निर्माण और मूल्य प्रणाली और रचनात्मकता वाले नागरिकों के विकास में मदद करने के लिए आवश्यक तत्व है**
- **कला और संस्कृति एक समृद्ध और शांतिपूर्ण दुनिया के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरह ही महत्वपूर्ण है**

जम्मू। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने अमर महल पैलेस, जम्मू में हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट (एचटीसीटी) द्वारा आयोजित तवी महोत्सव के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में अमर महल संग्रहालय और पुस्तकालय के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह की शुरूआत भी हुई।

अपने संबोधन में, उपराज्यपाल ने डॉ. करण सिंह और हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े सभी लोगों को इस अनोखे महोत्सव के आयोजन और कला, साहित्य और इतिहास में नए विचारों को साझा करने और उजागर करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और चिकित्सकों को एक साथ लाने के लिए बधाई दी।

उपराज्यपाल ने कहा, एक प्रबुद्ध समाज के निर्माण और मूल्य प्रणाली और रचनात्मकता के साथ नागरिकों के विकास में मदद करने के लिए कला आवश्यक तत्व है।

कला और संस्कृति एक समृद्ध और शांतिपूर्ण दुनिया के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समान ही महत्वपूर्ण है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने नई सुविधाएं प्रदान की हैं और मानव समाज के काम करने और रहने के तरीके को फिर से परिभाषित किया है। लेकिन आधुनिक साधन कला और संस्कृति की समृद्ध और जीवंत परंपरा के बिना अधूरे हैं। हमें प्रौद्योगिकी और कला के बीच एक अच्छा संतुलन बनाने की जरूरत है।

हमारी सभ्यता को जीवंत बनाने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए आविष्कारों की भूमिका अतुलनीय है। इसलिए, मेरा मानना है कि समाज को वैज्ञानिकों के साथ-साथ कलाकारों और अध्यात्मवादियों की भी जरूरत है। उपराज्यपाल ने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकास भी विरासत भी के संकल्प के साथ काम करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

उन्होंने स्थानीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने में कलाकारों और बुद्धिजीवियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। समाज का आर्थिक विकास कला और संस्कृति द्वारा संचालित होता है। सतत विकास के लिए हमें अधिक रचनात्मक नेताओं की आवश्यकता है। युवा पीढ़ी को हमारी संस्कृति और मूल्यों से जोड़ने के हमारे प्रयासों को और गहरा किया जाना चाहिए, उपराज्यपाल ने कहा। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर की कलात्मक, सांस्कृतिक और भाषाई विरासत की समृद्ध विविधता और विशिष्टता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए समर्पित उपायों को भी साझा किया।

इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. करण सिंह; ट्रस्ट के ट्रस्टी और सदस्य और श्री विक्रमादित्य सिंह, श्री अजातशत्रु सिंह, डॉ. ज्योत्सना सिंह, सुश्री रितु सिंह, श्री मार्तंड सिंह सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्ति; पुलिस और नागरिक प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और प्रसिद्ध कलाकार उपस्थित थे।

स्थायी विकास के लिए हमें अधिक रचनात्मक नेताओं की आवश्यकता है राज्यपाल।

निदेशक स्कूल शिक्षा कश्मीर ने जोन वैलू, अनंतनाग में मेगा नामांकन अभियान शुरू किया

दिव्य भारत संवाददाता

अनंतनाग। सरकारी स्कूलों में छात्र नामांकन को बढ़ावा देने के लिए, निदेशक स्कूल शिक्षा कश्मीर), डॉ. जी. एन. इटू ने आज क्लस्टर गडोल, जोन वैलू, जिला अनंतनाग से मेगा नामांकन अभियान की शुरूआत की।

इस अभियान को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिसमें 300 से अधिक छात्रों और नए प्रवेशकों ने जोन वैलू, अनंतनाग के विभिन्न सरकारी स्कूलों में प्रवेश प्राप्त किया।

नामांकन अभियान का उद्देश्य सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और बेहतर बुनियादी ढांचे, समर्पित शिक्षण कर्मचारियों और छात्र-अनुकूल शिक्षण वातावरण का प्रदर्शन करके सरकारी स्कूलों में जनता का विश्वास बढ़ाना है।

स्वच्छ भारत अभियान परियोजना के लिए समय सीमा निर्धारित करें : मुख्य सचिव

दिव्य भारत संवाददाता

जम्मू। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने आज यहां क्लीन इंडिया मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) की तैयारी के तहत रापू की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को इस योजना के तहत प्रत्येक परियोजना के लिए समयसीमा तय करने के लिए प्रेरित किया।

बैठक में आयुक्त सचिव, एचएंडयूडीडी के स्थान पर जेके प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष ग्रामीण स्वच्छता गोदाम और एसबीएम-शहरी के प्रबंध निदेशक सहित अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए।

मुख्य सचिव ने 2035 तक उत्पादन होने वाले उद्योगों के प्रबंधन के लिए प्रस्तावित रोजगार घटक की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार तैयार किया गया स्क्रैप लागू करने योग्य है, इसलिए इसके सफल कार्यान्वयन के लिए समय सीमा निर्धारित करने के लिए आगे की विचार प्रक्रिया की आवश्यकता है।

उन्होंने राजधानी, शहरों के साथ-साथ प्रत्येक यू.एल.बी. में निर्मित टुकड़ों की मात्रा पर ध्यान दिया। वे यहां प्रत्येक प्रकार के चॉकलेट के प्रभावशाली उपचार और प्रबंधन के लिए अंतिम समाधान की मांग के लिए उत्पन्न हुए। डुल्लू ने कहा कि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधि के लिए कभी धन भी बाधा नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित लागत अगले कुछ वर्षों में सुरक्षा की जाने वाली सीमा के अंदर है। उन्होंने विभाग को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए निर्धारित समय सीमा को पूरा करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यार्थियों को उनके उपचार और ग्रुप के स्थानों तक ले जाने के लिए विरासती क्रीड़ाओं, प्लास्टिक क्रीड़ाओं, ग्रे वॉटर, प्रयुक्त किए गए पानी, प्लास्टिक क्रीड़ाओं और निर्माण एवं विध्वंस (सीएंड) विभागों को शामिल करने पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा, मुख्य सचिव ने उन्हें अमृत 2.0 के सिद्धांत के अनुसार जहां भी संभव हो, इसके तहत सहायकों को शुरू करने के विकल्प तलाशने को कहा। उन्होंने कैपेक्स के तहत उन लेखों को शामिल करने का भी सुझाव दिया, जहां प्रस्तुति का समर्थन करने के लिए कोई अन्य योजना नहीं है। बैठक में एचएंडयूडी के कमिश्नर सचिव मनदीप कौर ने कहा कि यह नॉर्थ ईस्ट कंपनी लिमिटेड के लिए एक नया रोडमैप है और अगले 10 वर्षों के लिए शहर एनजीटी के लिए एक रोडमैप भी है। उन्होंने सुझाव दिया कि पैनल को दशकीय वृद्धि दर पर केंद्रित किया गया है और इस पैनल को प्रतिदिन तैयार करने पर ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस अद्यतन योजना को तैयार करने के लिए टाइम कंपनी, उपचार और स्टूडियो के अलावा अन्य विद्वानों के अलावा गिरोह के उपचार पर भी विचार किया गया है। एसबीएम (यू) के एमडी देवांश यादव ने बैठक में बताया कि उम्मीद है कि 2035 तक यूटी के शहरी क्षेत्र की आबादी लगभग 51.50 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जिससे 2481 टीपीडी कचरा पैदा होगा। उन्होंने प्रत्येक यूएलबी और कैंटोनमेंट बोर्ड को बनने वाले दांतों की मात्रा के अनुसार अलग-अलग करने और 2035 तक इसके प्रबंधन के लिए आवश्यक सुविधाओं के बारे में भी बताया। उन्होंने नगर निगमों, जम्मू/कश्मीर के यूएलबी और जम्मू एवं कश्मीर कैंटोनमेंट बोर्डों में रियल एस्टेट का विवरण प्रस्तुत किया। बैठक में डोर टु डोरा के लिए आवश्यक सुविधाओं की भी तलाश की गई। यूटी के विभिन्न नगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं के तहत प्रस्तावित लोगों में सभी वर्षों के लिए इसकी सहकारी समितियों के सहयोग के बारे में खुलासा किया गया है। विरासत के चर्चों के बारे में, यह कहा गया है कि नगर डायनासोर द्वारा कुल 26,11,102 पर डंके की चोट के बारे में जानकारी दी गई है।

इसमें से, 3,91,604 मिक्सर टन का पहले ही उपचार किया जा चुका है और शेष 22,19,498 मिक्सर टन का इस योजना के तहत उपचार करना आवश्यक है, जिसके लिए अधिकांश स्थान पर काम दिए जा चुके हैं या टेंडर जारी किए जा चुके हैं। बैठक में सॉलिड, तरल, एमएसएम, प्लास्टिक और विरासती कंपनी प्रबंधन के विभिन्न मॉडलों पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि सभी 75 यूएलबी के लिए विस्तृत आख्या तैयार करने के लिए पीडीएमसी को काम पर रखने के लिए निविदा जारी की गई है और इस उद्देश्य के लिए 4 शानदार बोलियां प्राप्त की गई हैं।

उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों से बात की

दिव्य भारत संवाददाता

जम्मू। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने आज राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) स्वयंसेवकों से बातचीत की, जिन्होंने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस शिविर 2025 में भाग लिया था।

एनएसएस स्वयंसेवकों ने समन्वयक डॉ. हेमा गंडोत्रा, जम्मू विश्वविद्यालय और डॉ. अमित पाल, क्लस्टर विश्वविद्यालय, जम्मू के साथ गणतंत्र दिवस शिविर में अपने अनुभव साझा किए।

उपराज्यपाल ने गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए एनएसएस स्वयंसेवकों को बधाई दी। उन्होंने उनसे स्थानीय समुदाय और पूरे राष्ट्र के विकास में योगदान देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी जारी रखने को कहा।

निदेशक स्कूल शिक्षा कश्मीर ने जोन वैलू, अनंतनाग में मेगा नामांकन अभियान शुरू किया।

कश्मीर घाटी में शीतकालीन अवकाश के बाद स्कूल खुले

दिव्य भारत संवाददाता

श्रीनगर। कई महीनों के शीतकालीन अवकाश के बाद स्कूलों के फिर से खुलने पर, स्कूल शिक्षा निदेशक कश्मीर , डॉ. जीएन इटू ने आज अनंतनाग जिले के दूरदराज के इलाके में सरकारी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल कोकरनाग की सुबह की प्रार्थना में भाग लिया और बच्चों के साथ स्कूल खुलने की खुशी साझा की।

इस अवसर पर, स्कूल शिक्षा निदेशक कश्मीर ने बच्चों से उनकी मातृभाषा में बात की और शीतकालीन अवकाश के दौरान विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी ली।

डीएसईके ने शिक्षकों को संबोधित किया और उनसे बच्चों को नैतिक शिक्षा देने, उनके लिए रोल मॉडल बनने और जल निकायों की रक्षा करने के अलावा आसपास के वातावरण को साफ रखने के लिए कहा।

डॉ. इटू ने शिक्षकों से समाज की वर्तमान चुनौतियों के मद्देनजर विशेष रूप से बुधवार को बच्चों को नशे के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करने और बच्चों के चरित्र निर्माण में अपनी पूरी भूमिका निभाने का आग्रह किया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को मोबाइल फोन का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए ताकि उनके दिमाग पर इसका नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

पुंछ में सतत अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए उपायुक्त ने आरआरआर सेंटर का शुभारंभ किया

दिव्य भारत संवाददाता

पुंछ। पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पुंछ के उपायुक्त विकास कुंडल ने आज 'रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल (आरआरआर) सेंटर' का उद्घाटन किया, जो एक अग्रणी पहल है जिसका उद्देश्य परिपत्र अर्थव्यवस्था सिद्धांतों और सतत अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना है। नव स्थापित आरआरआर सेंटर अपशिष्ट पदार्थों के संग्रह, छंटाई और वितरण के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में काम करेगा, जो प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक कचरे, कपड़े और फर्नीचर जैसे त्यागे गए घरेलू सामानों के पृथक्करण, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करेगा। यह पहल लैंडफिल कचरे को कम करने और अनुचित अपशिष्ट निपटान से जुड़े पर्यावरणीय खतरों को कम करने के लिए डिजाइन की गई है।

उद्घाटन के दौरान, डिप्टी कमिश्नर ने संधारणीय प्रथाओं को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, आरआरआर केंद्र की स्थापना अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन संरक्षण की दिशा में एक प्रगतिशील पहल है। संधारणीय प्रथाओं को अपनाकर, हम पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं और रीसाइक्लिंग उद्योगों में शामिल अपशिष्ट श्रमिकों और उद्यमियों के लिए आर्थिक अवसर पैदा कर सकते हैं। पुंछ की नगर परिषद नागरिकों को इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। जागरूकता अभियान, स्कूल अभियान और घर-घर जाकर कचरा संग्रहण कार्यक्रम शुरू करने की योजनाएँ चल रही हैं, जिससे गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों को अपशिष्ट कम करने के प्रयासों में शामिल किया जा सके। आरआरआर केंद्र के सफल शुभारंभ के साथ, नगर परिषद पुंछ में स्वच्छ शहर बनाने और संधारणीय अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए अपने समर्पण की पुष्टि करती है। नागरिकों को इस महत्वपूर्ण पहल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पुनः प्रयोज्य वस्तुओं का दान करके, कचरे को अलग करके और रीसाइक्लिंग प्रयासों का समर्थन करके योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

Page-06_Layout 1 3/8/2025 2:23 AM Page 1

यूक्रेन पर चल रहे रूसी हमले के बीच यूक्रेन के युद्धबंदियों के रिश्तेदार कीव में संयुक्त राज्य अमेरिका के दूतावास के सामने, रूस के साथ किसी भी शांति वार्ता या समझौते से पहले सभी युद्धबंदियों की रिहाई की मांग करते हुए एक रैली में शामिल हुए।

अमेरिकी सेना में चीनी सेंधमारी, दो सक्रिय सैनिक और एक पूर्व सैनिक ने ड्रैगन को दी सीक्रेट जानकारी

वाशिंगटन। दुनिया की सबसे ताकतवार सेना में शुमार अमेरिकी सेना में चीनी सेंधमारी का खुलासा हुआ है। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई (एफबीआई) ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी के नेतृत्व में यूएस आर्मी के दो सक्रिय सैनिकों और एक पूर्व सैनिक को गिरफ्तार किया है। इन सैनिकों पर सरकारी संपत्ति की चोरी और रिश्वतखोरी की साजिश में शामिल होने का आरोप है। यहां चौंकाने वाली बात ये है कि इन अमेरिकी सैनिकों ने चीन के हाथों कई खुफिया जानकारी बेची हैं।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान जियान झाओ, ली तियान और रुओयु दुआन के रूप में हुई है। जियान झाओ और ली तियान जॉइंट बेस लुईस-मककॉर्ड में तैनात सक्रिय सैनिक हैं, जबकि रुओयु दुआन पूर्व सैनिक है। रिपोर्ट के अनुसार, तियान और दुआन पर ओरेगन जिला में रिश्वतखोरी और सरकारी संपत्ति की चोरी की साजिश रचने का आरोप लगा है। वहीं, झाओ पर वाशिंगटन के पश्चिमी जिला में राष्ट्रीय रक्षा जानकारी को अनधिकृत व्यक्तियों तक पहुंचाने की साजिश, रिश्वतखोरी और सरकारी संपत्ति की चोरी के आरोप हैं।

पुलिस की चार्जशीट में कहा गया है कि जुलाई 2024 से लेकर गिरफ्तारी तक, झाओ ने कई संवेदनशील हार्ड ड्राइव को कलेक्ट और चीन में स्थित व्यक्तियों को बेचने की साजिश रची। इन हार्ड ड्राइव पर सीक्रेट और टॉप सीक्रेट का निशान लगा था, फिर भी सैनिक ने इन्हें बेचा। इन हार्ड ड्राइव के बदले में झाओ को करीब 10,000 डॉलर प्राप्त हुए। इसके अलावा, झाओ पर अमेरिकी सरकार से चुराए गए एक एन्क्रिप्शन-सक्षम कंप्यूटर को बेचने का भी आरोप है।

अमेरिकी अटॉर्नी जनरल बॉन्डी ने कहा, आज गिरफ्तार किए गए आरोपी हमारे देश के साथ विश्वासघात करने, अमेरिका की रक्षा क्षमताओं को कमजोर करने और चीन जैसे हमारे विरोधियों को सशक्त करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। उन्हें त्वरित, कठोर न्याय का सामना करना पड़ेगा।

वहीं एफबीआई निदेशक काश पटेल ने घटना पर कहा, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के तहत फल-फूल सकता है, लेकिन हमारे सैनिकों में इस बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वे खुद संवेदनशील सैन्य जानकारी के संरक्षक हैं। इस मामले की जांच एफबीआई के पोर्टलैंड और सिएटल फील्ड कार्यालयों और अमेरिकी सेना काउंटरइंटेलिजेंस कमांड द्वारा की गई, जिसमें सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी), डाक निरीक्षण सेवा और नौसेना आपराधिक जांच सेवा ने सहायता प्रदान की। सेना काउंटरइंटेलिजेंस कमांड के कमांडिंग जनरल ब्रिगेडियर जनरल रेट आर. कॉक्स ने कहा, ये गिरफ्तारियां हमारी सेना और राष्ट्र के सामने बढ़ते विदेशी खुफिया खतरे को रेखांकित करती हैं।

एक पहिए के बगैर विमान की काठमांडू में लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित

काठमांडू, (हि.स.)। नेपाल के हवाई क्षेत्र में एक विमान बिना एक पहिए के जनकपुर से काठमांडू में लैंड किया और पायलट को इस बात का पता भी नहीं चला। हालांकि विमान सुरक्षित लैंड हुआ और सभी यात्री सुरक्षित हैं।

जनकपुर से काठमांडू के लिए आए बुद्ध एयर के विमान के एक पहिया के बगैर लैंडिंग कराने के कारण नेपाल की हवाई सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। गुरुवार शाम बुद्ध एयर का विमान संख्या व4 508 जनकपुर से शाम 16:39 बजे रवाना हुआ और 17:05 बजे काठमांडू में लैंड हुआ। इस दौरान विमान का एक पहिया नहीं दिखा। इस बात का पता पायलट को तब हुआ जब अगले गंतव्य के लिए उड़ान भरने से पहले विमान की जांच की जा रही थी।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुल ने बताया कि पायलट को पोस्ट फ्लाइट चेक के दौरान नोज गियर (अगला पहिया) नहीं होने की खबर लगी। प्रवक्ता ने बताया कि इस पहिए के बारे में तत्काल पता लगाने के लिए जनकपुर विमानस्थल को सूचना दी गई। जनकपुर विमानस्थल में ढूंढ़ने पर पता चला कि इस विमान का एक पहिया वहीं रनवे पर पड़ा था और उसके नॉट वोल्ट टूटे हुए थे। ज्ञानेन्द्र भुल ने बताया कि रनवे पर यू टर्न लेते समय यह पहिया निकल गया था। विमान के पुराने मॉडल का होने के कारण पहिया की तरफ न तो कैमरा लगा होता है और ना ही सेंसर की सुविधा है, जिस कारण पायलट को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई।

प्राधिकरण के प्रवक्ता ने कहा कि इस घटना के तुरंत बाद बुद्ध एयर के जहाज को ग्राउंडेड कर इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

नेपाल की ओली सरकार ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को अपने दायरे में रहने की दी नसीहत

काठमांडू, (हि.स.)। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की बढ़ती सक्रियता और देशभर में उनके पक्ष में सड़कों पर हो रहे प्रदर्शन के बीच केपी शर्मा 'ओली' की सरकार ने उन्हें अपने दायरे में रहने की नसीहत दी है। सरकार ने कहा है कि अब देश में राजतांत्रिक व्यवस्था का लौटना संभव नहीं है।

लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश की जाएगी तो किसी भी कीमत पर उसको सफल नहीं होने दिया जाएगा।

कुछ दिनों पहले नेपाल के प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र ने देशवासियों के नाम वीडियो संदेश जारी करते हुए उन्हें समर्थन देने की अपील की थी। इसके बाद से ही उनके समर्थक दल देशभर में प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी काठमांडू सहित कई शहरों में हुए प्रदर्शन के बाद इस पर सरकार ने अब प्रतिक्रिया दी है।

नेपाल सरकार के प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि पूर्व राजा और उनके समर्थकों द्वारा सड़क पर उछलकूद करने से देश में राजतंत्र दोबारा स्थापित नहीं हो सकता है। उन्होंने पूर्व राजा को चेतावनी देते हुए कि उनको अपने दायरे में रहना चाहिए।

पूर्व सूचना तथा संचार मंत्री रहे गुरुंग ने कहा कि यदि देश में लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश की जाएगी तो किसी भी कीमत पर उसको सफल नहीं होने दिया जाएगा।

पूर्व राजा के पक्ष में बढ़ते जनसमर्थन पर कटाक्ष करते हुए सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि देशवासियों को पूर्व राजा के झांसे में नहीं आना चाहिए। जो व्यक्ति अपने परिवार और दरबार की सुरक्षा नहीं कर सकता, उसे देश की सुरक्षा के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि नेपाल एक उदार लोकतांत्रिक देश है। इसके कारण पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सम्मान और सरकारी सुरक्षा के साथ देश में रह रहे हैं।

गुरुंग ने कहा कि यदि किसी और देश में राजा को सत्ता छोड़ने की नौबत आती तो वह सीधे जेल में होता या देश छोड़ कर जा चुका होता, लेकिन नेपाल सरकार उन्हें पूरे सम्मान के साथ और सरकारी सुरक्षा देकर यहां रहने दे रही है, इसका उन्हें एहसान मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि नेपाल में राजतांत्रिक व्यवस्था का अब किसी भी स्वरूप में लौटना संभव नहीं है।

व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट के साथ वाशिंगटन, यू.एस. में व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग के बाहर समाचार मीडिया के सदस्यों से बात करते यू.एस. मध्य पूर्व के दूत स्टीव विटकॉफ।

एथेना लैंडर चंद्रमा पर उतरा थोड़ी देर बाद हो गया गायब

वाशिंगटन। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी इंट्यूएटिव मशीन्स का एथेना लैंडर गुरुवार को चांद पर उतरा गया। इसकी पुष्टि नासा ने की। अब कहा जा रहा है कि इसकी स्थिति की जानकारी नहीं मिल रही है। वहीं नासा ने लाइव टेलिकास्ट भी बंद कर दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पता नहीं चल पा रहा कि लैंडर चांद की सतह पर सीधा खड़ा है या नहीं।

मीडिया रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि मिशन की पुष्टि को लेकर समय लग सकता है। मिशन के डायरेक्टर और कंपनी के टिम क्रेन भी स्पष्ट नहीं कर पाए कि मिशन चंद्रमा पर उतरा भी है या नहीं। उन्होंने कहा कि लैंडर की स्थिति का पता लगाने की कोशिश जारी है। अधिकारियों का कहना है कि सतह पर उतरने के बाद भी लैंडर से संपर्क साधा गया था। पिछली बार जब इंट्यूटिव मशीन्स नामक इस कंपनी ने एक साल पहले चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारा था, तो वह तिरछा होकर गिर गया था।

कंपनी का सबसे नया एथेना लैंडर योजना के मुताबिक चंद्रमा की कक्षा से बाहर निकल गया है। उसमें एक आइस ड्रिल, एक ड्रोन और दो रोवर लगे हैं। एक घंटे तक ऐसा लगा कि यह लैंडर अच्छी तरह उतर रहा है लेकिन मिशन कंट्रोल को उसके उतरने की पुष्टि करने में समय लगा। उन्होंने कहा कि हम यह मूल्यांकन कर रहे हैं कि सतह पर हमारा झुकाव कितना है।

अधिकारियों ने बताया कि एथेना कंट्रोलर से संपर्क कर रहा था और सौर ऊर्जा पैदा कर रहा था लेकिन लैंडिंग के 20 मिनट बाद भी क्रेन यह पुष्टि करने में असमर्थ था कि लैंडर के साथ सब कुछ ठीक है या नहीं। नासा और इंट्यूटिव मशीन्स ने इस लैंडिंग का सीधा प्रसारण बंदर करते हुए कहा कि बाद में वे और जानकारियां साझा करेंगे। गौरतलब है कि पिछले साल, इंटुएटिव मशीन्स ने इतिहास रचा था जब इसके पहले चंद्र लैंडर ओडीसियस ने चंद्र सतह पर एक नरम टचडाउन किया, जो 50 से ज्यादा सालों में चंद्र सतह पर उतरने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान था।

नासा के मुताबिक लैंडर वैज्ञानिक उपकरणों से भरा हुआ है और चंद्रमा के पर्यावरण को और समझने के लिए नासा की विज्ञान जांच और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों को ले जायेगा और चंद्रमा की सतह पर भविष्य के मानव मिशनों की तैयारी में मदद मिलेगी। आईएम-2 चंद्र गतिशीलता, संसाधन पूर्वेक्षण और उप-सतह सामग्री से अस्थिर पदार्थों के विश्लेषण को प्रदर्शित करने के लिए तैयार कर रहा है, जो पृथ्वी से परे जल स्त्रोतों को उजागर करने की दिशा में एक अहम कदम है।

इजराइल ने फिलिस्तीनियों की कैद से 10 भारतीय मजदूरों को छुड़ाया

तेल अवीव। इजराइली अधिकारियों ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की कैद से 10 भारतीय मजदूरों को छुड़ाया है। सभी को इजराइल लाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, फिलिस्तीनियों ने इन भारतीयों को मजदूरी के काम का झांसा देकर अल-जायम गांव में बुलाया था।

इसके बाद भारतीय मजदूरों को बंधक बनाकर सभी के पासपोर्ट जब्त कर लिए थे। फिलिस्तीनी इन पासपोर्ट का इस्तेमाल कर अवैध रूप से इजराइल में घुसने की कोशिश में थे। इजराइली अधिकारियों ने 6 मार्च की रात वेस्ट बैंक में ऑपरेशन चलाकर इन सभी बंधकों को छुड़ाया। इजराइल में भारतीय दूतावास ने इसकी जानकारी दी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। भारतीय दूतावास इजराइली अधिकारियों के संपर्क में हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल से अब तक करीब 16 हजार भारतीय मजदूर इजराइल पहुंचे हैं। मई 2023 में इजराइल और भारत के बीच एक श्रम समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के तहत 42,000 भारतीय मजदूरों को इजराइल में रोजगार दिया जाना था।

मस्क विभागों के अध्यक्ष नहीं, उन्हें कर्मचारियों को निकालने का अधिकार नहीं : ट्रंप

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैबिनेट को बताया कि उनके सलाहकार एलन मस्क उनके विभागों के अध्यक्ष नहीं हैं और उन्हें संघीय कर्मचारियों को निकालने का अधिकार नहीं है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप ने कहा कि टेस्ला के प्रमुख केवल विभागों को सलाह देने के लिए हैं, लेकिन वे कर्मियों और नीतियों पर एकतरफा फैसला लेने के लिए अधिकृत नहीं हैं। एलन मस्क इस निर्देश से सहमत थे और बैठक में उपस्थित थे। वहीं मस्क ने कहा कि नौकरी से निकाले जाने के वो जिम्मेदार नहीं हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क ने ट्रंप के पहले कैबिनेट बैठक में पिछले सप्ताह इबोला रोकथाम फंडिंग को गलती से रद्द करने पर भी अपनी गलतियों को स्वीकार किया। यह घटनाक्रम मस्क और उनकी नई बनाई गई डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशियेंसी (डॉज) के साथ जुड़ा हुआ है, जो फेडरल कर्मचारियों की छंटनी समेत लागत घटाने के उपायों पर काम कर रहा है। एलन मस्क ने खुद सरकारी कर्मचारियों को नहीं निकाला। उन्हें ऐसा करने का कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन डॉज के प्रयासों के कारण महत्वपूर्ण संख्या में छंटनी और इस्तीफे हुए हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है, जबकि 75 हजार ने स्वैच्छिक तरीके से निकालने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। इन छंटनियों का मुख्य रूप से असर उन कर्मचारियों पर पड़ा है, जो प्रोबेशनरी स्थिति में थे। उनके पास नागरिक सेवा संरक्षण कम होता है, जिससे उन्हें हटाना आसान है। इन छंटनियों का असर कई एजेंसियों पर पड़ा है, जिनमें आंतरिक राजस्व सेवा, ऊर्जा मंत्रालय, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन्स अफेयर्स और अन्य शामिल हैं।

मस्क ने रिपब्लिकन सांसदों के सामने इन मामलों को लेकर कहा कि सरकार के आकार को कम करने के लिए हुई कर्मचारियों की बर्खास्तगी के लिए वह जिम्मेदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह की बातचीत के बाद यह फैसला उन्होंने संघीय एजेंसियों पर छोड़ दिया था। ट्रंप के सबसे प्रभावशाली सलाहकारों में से एक मस्क का संदेश ऐसे समय में सामने आया है जब रिपब्लिकन लोग मस्क के दक्षता विभाग के कामों का समर्थन कर रहे हैं लेकिन निजी तौर पर इसक विरोध कर रहे हैं। क्योंकि यह कटौती देश के कई समुदायों पर असर डाल रही है। मस्क के साथ बैठक करने वाले एक प्रतिनिधि ने कहा कि मस्क लोगों को नौकरी से नहीं निकालते हैं।

काठमांडू में होली पर्व की हुई औपचारिक शुरुआत

काठमांडू, (हि.स.)। राजधानी काठमांडू के मूल निवासी कहे जाने वाले नेवार समुदाय के लोगों ने रंगों के त्योहार होली की औपचारिक शुरूआत शुक्रवार से कर दी है। बसंतपुर दरबार स्क्वायर में नेवार समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर शुभ मुहूर्त पर रंगीन झंडा फहराने के साथ ही एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाया।

फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होने वाला रंगों का त्योहार होली आज से शुरू होकर पूर्णिमा के दिन तक खेला जाता है। बसंतपुर में रहे हनुमान ढोका दरबार स्क्वायर पर नेवार समुदाय ने रंगीन बांस का झंडा फहराने के साथ ही इसकी शुरूआत कर दी है। नेपाल में यह परंपरा दरबार स्क्वायर के भीतर राजगद्दी बैठक के दक्षिण की ओर तीन स्तर वाले ध्वज के निर्माण के बाद शुरू होती है। आज शुभ मुहूर्त पर नेवार समुदाय के लोगों ने रंगीन झंडा फहराने के साथ ही एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। शुक्रवार को दिन भर नेवार समुदाय के लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर इस पर्व का आनंद लेने वाले हैं।

नेवार समुदाय की बहुलता वाले क्षेत्र काठमांडू के बसंतपुर दरबार स्क्वायर के अलावा ललितपुर के कृष्ण मंदिर पाटन दरबार स्क्वायर और भक्तपुर दरबार स्क्वायर में भी इसी तरह का ध्वज फहरा कर होली की शुरूआत की जाती है। उधर, पशुपतिनाथ मंदिर में भी एक रंगीन ध्वज लगाया जाता है।

गाजा शहर के उत्तर में नष्ट हो चुकी इमारतों के मलबे के बीच रमजान इफ्तार के लिए एकत्रित होते लोग।

तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यार्पण का रास्ता साफ, अमेरिकी अदालत ने खारिज की फैसले पर रोक की मांग

वॅशिंगटन, (हि.स.)। मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपित तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। भारत प्रत्यर्पण के फैसले पर रोक लगाने की उसकी मांग अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। तहव्वुर ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर कहा था कि उसे भारत प्रत्यर्पित न किया जाए। उसने इमरजेंसी स्टे की मांग करते हुए कहा था कि भारत भेजे जाने पर उसे टॉर्चर किया जा सकता है। वह मुस्लिम है और पाकिस्तानी मूल का है इसलिए उसे ज्यादा खतरा है। उसने अपने खराब स्वास्थ्य का भी हवाला देते हुए प्रत्यार्पण पर रोक की मांग की थी। पाकिस्तान मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा (64) को लॉस एंजिलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। वह 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली का करीबी है। अमेरिका में उसे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने का दोषी पाया गया और भारत लंबे समय से उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था। पिछले महीने व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि तहव्वुर राणा को भारत भेजा जाएगा और वह भारत जाकर न्याय का सामना करेगा। इससे पहले जनवरी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी थी, क्योंकि कोर्ट ने मामले में उसकी समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी। 26 नवंबर 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने मुंबई में लगभग 60 घंटे तक चले हमले में 166 निर्दोष लोगों की जान ले ली थी।

Page-07_Layout 1 3/8/2025 2:24 AM Page 1

इंडियन वेल्स, सीए, यूएसए; जोआओ फोंसेका (बीआरए) ने इंडियन वेल टेनिस गार्डन में बीएनपी परिबास ओपन में जैकब फर्नले को हराने के दौरान अपने पहले दौर के मैच में शॉट मारा।

हमें ओलंपिक की मेजबानी करनी ही चाहिए : महेश भूपति

कोलकाता, (हि.स.)। ओलंपिक 15 बिलियन डॉलर (करीब 1.25 लाख करोड़ रुपये) का एक आयोजन है। भारत 2036 में इसकी मेजबानी करना चाहता है, लेकिन क्या यह एक तर्कसंगत विचार है, खासकर तब जब भारत खेलों की महाशक्ति नहीं है? इस पर टेनिस दिग्गज महेश भूपति का स्पष्ट जवाब 'हां' था।

रेवस्पोर्ट्ज.ट्रेलब्लेजर्स 3.0 कॉन्क्लेव में शुक्रवार को भूपति ने कहा, हमें 2036 या 2046 में ओलंपिक की मेजबानी करनी ही चाहिए। भूपति जानते हैं कि भारत में क्रिकेट को छोड़कर अन्य खेलों को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा, बीसीसीआई पैसा गांवों और ज़िलों तक पहुंचाता है। बीसीसीआई एक निजी संगठन है और उसके पास संसाधन हैं, लेकिन अन्य खेलों के पास यह सुविधा नहीं है। उन्होंने भारत की युवा टेनिस खिलाड़ी माया राजेश्वरन का उदाहरण दिया, जो फिलहाल स्पेन में राफेल नडाल की अकादमी में प्रशिक्षण ले रही हैं। भूपति ने कहा, टेनिस की दुनिया बहुत बड़ी है। हम यहां सिर्फ एक माया की बात कर रहे हैं, लेकिन स्पेन जैसे देशों में ऐसी 30-40 माया होती हैं। फिर भी, भूपति मानते हैं कि भारत को ओलंपिक की मेजबानी करनी चाहिए, क्योंकि इससे देश में खेलों के विकास को गति मिलेगी। स्क्वैश खिलाड़ी सौरव घोषाल ने भी इस विचार का समर्थन किया। उन्होंने कहा, यह बहुत जरूरी है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए हम ऐसा करें। पूर्व ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन और भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच पुलेला गोपीचंद ने भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में 107 पदक जीतने के बावजूद उस सफलता को आगे नहीं बढ़ा सका। तब हमारे पास बुनियादी ढांचा नहीं था, लेकिन अब हालात पहले से बेहतर हैं। वहीं, वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष अदिले सुमारीवाला ने कहा, हमें उन खेलों पर ध्यान देना चाहिए, जिनमें कई पदक जीतने की संभावनाएं होती हैं। कॉन्क्लेव में सभी ने इस बात पर सहमति जताई कि भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी करनी चाहिए, ताकि खेलों के विकास की गति को तेज किया जा सके।

भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए केंद्र और राज्यों का समन्वित प्रयास जरूरी : मांडविया

तेलंगाना, (हि.स.)। भारत की 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक तैयारियों और 2036 ओलंपिक की मेजबानी को मजबूत करने के उद्देश्य से दो दिवसीय चिंतन शिविर लगाया गया। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में लगे इस शिविर में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों, वरिष्ठ खेल प्रशासकों, सरकारी अधिकारियों और खेल विशेषज्ञों ने भाग लिया।

डॉ. मांडविया ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना है कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी करे और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी राज्यों को मिलकर प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा, चिंतन शिविर प्रधानमंत्री मोदी की सुशासन की सोच से प्रेरित है, जहां हम मिलकर खेलों के विकास की दिशा में एक ठोस रणनीति तैयार कर सकते हैं। डॉ. मांडविया ने कहा, भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए खेलों का सुव्यवस्थित और समन्वित विकास आवश्यक है। खेल राज्य का विषय है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत प्रयास हमें खेल महाशक्ति बनने में मदद कर सकते हैं।

चिंतन शिविर में मुख्य रूप से प्रतिभा पहचान, कोचिंग प्रणाली, खेल बुनियादी ढांचे के विकास और खेलों की सतत प्रगति जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, हरियाणा, बिहार, केरल, उत्तराखंड, गुजरात और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव साझा किए और खेल विकास को गति देने के लिए एक-दूसरे से सीखने की जरूरत पर बल दिया गया।

बैठक में खेलो इंडिया कार्यक्रम के प्रभाव पर भी विस्तार से चर्चा हुई। डॉ. मांडविया ने बताया कि अब तक 2,800 से अधिक खेलो इंडिया अकादमियां स्थापित की जा चुकी हैं, जबकि 1,045 खेलो इंडिया केंद्रों में से 937 पूरी तरह कार्यरत हैं।

उन्होंने कहा, हमें अपनी खेल प्रतिभाओं को खोने नहीं देना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खिलाड़ियों की पहचान और प्रबंधन, तथा राष्ट्रीय खेल संघों की सक्रिय भागीदारी से ओलंपिक मिशन को मजबूत किया जा सकता है। डॉ. मांडविया ने यह भी घोषणा की कि खेलो इंडिया के तहत नए खेलों को बढ़ावा देने के लिए 'बीच गेम्स', 'वॉटर स्पोर्ट्स' और 'स्वदेशी खेलों' को शामिल किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर अधिक भागीदारी सुनिश्चित होगी।

शिविर में राष्ट्रीय खेल संघों में पारदर्शिता बढ़ाने और चयन प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने पर भी जोर दिया गया। इसके साथ ही, माता-पिता का विश्वास जीतने के लिए बेहतर संरचनाएं विकसित करने और खेल को करियर के रूप में अपनाने के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की रणनीति पर चर्चा हुई।

खेल अवसंरचना के विकास को लेकर राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों, मंत्रालयों और निजी क्षेत्र के सहयोग से खेल परिसरों का प्रभावी उपयोग करने पर जोर दिया गया।

इसके तहत जिला स्तरीय खेल विद्यालय स्थापित करने और मौजूदा स्कूलों को अपग्रेड करने पर भी चर्चा हुई, ताकि जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की खोज और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जा सके।

बैठक के दौरान प्रतिभागियों के लिए पद्मभूषण दाजी के नेतृत्व में ध्यान सत्र आयोजित किया गया, जिससे मानसिक एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की कला पर जोर दिया गया।

इसके अलावा, शाम को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाला एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पारंपरिक संगीत, नृत्य और कलात्मक प्रस्तुतियों ने देश की विविधता और खेल भावना को जीवंत कर दिया।

इस चिंतन शिविर से निकले विचारों और रणनीतियों के आधार पर भारत की ओलंपिक तैयारियों को एक नई दिशा दी जाएगी, जिससे 2036 ओलंपिक की मेजबानी के सपने को साकार किया जा सके।

यूरोपा लीग सॉकर फुटबॉल के राउंड ऑफ में पहले चरण में एएस रोमा बनाम एथलेटिक बिलबाओ मैच में एएस रोमा के जियानलुका मैनसिनी और निकोलो पिसिली एथलेटिक बिलबाओ के एंडर हेरेरा के साथ एक्शन में ।

दिल्ली

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने साहित्योत्सव 2025 का किया उद्घाटन

नई दिल्ली, (हि.स.)। साहित्य अकादेमी के एशिया का सबसे बड़े साहित्योत्सव का केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुक्रवार को उद्घाटन किया।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाला सबसे मजबूत तंतु साहित्य है। उन्होंने भारत के साहित्य की गतिशीलता और जीवंतता को उसकी विशेषता को बताते हुए कहा कि तकनीक के समय में अनुवाद के जरिए हमारा साहित्य अब वैश्विक होने लगा है। अब उस पर चर्चा प्रारंभ हो गई है। पूरी दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। उन्होंने भारतीय साहित्य को जीवन को सही दिशा देने वाला मानते हुए कहा कि इसकी भूमिका हर काल और परिदृश्य में प्रासंगिक रही है और आगे भी रहेगी। यह भारत की मनीषा ही है, जिसने अपनी पुरातनता को सदा नवीन बनाए रखते हुए यथार्थ से साक्षात्कार कर अनेक समस्याओं के निदान दिए हैं।

इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित कर साहित्य अकादेमी प्रदर्शनी 2024 का भी उद्घाटन किया। इस वार्षिक प्रदर्शनी में चित्रों तथा लेखों के विवरण से विगत वर्ष की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है।

साहित्य अकादेमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने मंत्री शेखावत का स्वागत शाल, पुस्तक और पुष्प देकर किया। अपने स्वागत वक्तव्य में माधव ने अकादेमी की पिछले वर्ष की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि साहित्य अकादेमी ने पिछले वर्ष 484 किताबें और 459 कार्यक्रम आयोजित किए।

साहित्योत्सव के पहले दिन आज 20 विभिन्न कार्यक्रमों में 100 से अधिक लेखकों ने सहभागिता की। इस दौरान आदिवासी कविता एवं कहानी-पाठ और पैनल चर्चा भी हुई। भारतीय साहित्य में नदियां, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की लोक संस्कृति, भारत की साहित्यिक कृतियों में लुप्त होता ग्रामीण समाज आदि विषयों पर भी विधिवत वक्तव्य दिए गए। अनेक सत्रों में बहुभाषी कविता और कहानी के पाठ किए गए। साहित्यप्रेमी श्रोताओं ने कहा कि सही मायनों में यह भारतीय भाषाओं का समग्र उत्सव है।

इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव अमृता प्रसाद साराभाई भी उपस्थित थीं।

साहित्योत्सव आज से यानी सात मार्च से 12 मार्च तक चलेगा। दूसरे दिन यानी शनिवार को साहित्य अकादेमी पुरस्कार 2024 अर्पण समारोह, कमानी सभागार में शाम 5.00 बजे होगा। इस पुरस्कार-अर्पण समारोह के मुख्यातिथि प्रख्यात अंग्रेजी नाटककार महेश दत्तानी होंगे। पुरस्कार समारोह के बाद प्रख्यात बांसुरी वादक राकेश चौरसिया द्वारा बांसुरी वादन प्रस्तुत किया जाएगा।

महिला सम्मान योजना पर आप नेताओं की बयानबाजी राजनीतिक हताशा का परिणाम : वीरेंद्र सचेदवा

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि महिला सम्मान योजना को लेकर नेता प्रतिपक्ष आतिशी सहित अन्य आम आदमी पार्टी नेताओं की दैनिक बयानबाजी उनकी राजनीतिक हताशा का परिणाम है।

वीरेंद्र सचदेवा ने एक बयान में कहा कि आआपा नेता भलीभांति जानते हैं कि जो दो सीएजी की रिपोर्ट सामने आईं हैं। वह आआपा संयोजक अरविंद केजरीवाल एवं उनके प्रमुख साथियों की लंबी जेल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए काफी है और ऐसे में अपने भ्रष्टाचार से जुड़ी सीएजी रिपोर्टों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए आआपा नेता हर दिन महिला सम्मान योजना पर नौटंकी कर रहे हैं।

वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आतिशी का महिला सम्मान योजना को लेकर पत्राचार केवल राजनीतिक दिखावा है। आतिशी को महिलाओं की सच्ची चिंता है, तो वह बताएं कि उनकी पार्टी ने पंजाब में 37 महीने से महिला सम्मान राशि क्यों नहीं दी? दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा महिला सशक्तीकरण एवं महिला सम्मान योजना के प्रति कृतसंकल्पित है और हम शीघ्र दोनों को पूरा करेंगे।

मेयर ने दिए राजधानी के अवैध स्पा, रेस्टोरेंट और होटलों पर कार्रवाई के निर्देश

नई दिल्ली , (हि.स.)। दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे स्पा, रेस्टोरेंट और होटलों की शिकायत मिलने पर मेयर महेश कुमार खिंची ने निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों को अवैध रूप से चल रहे इन प्रतिष्ठानों की सूची देने का निर्देश दिया गया है। ये प्रतिष्ठान निगम को कोई लाइसेंस शुल्क नहीं देते हैं, जिससे निगम को राजस्व का नुकसान भी होता है।

मेयर महेश कुमार खिंची ने शुक्रवार को निगम मुख्यालय में दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे स्पा, रेस्टोरेंट एवं ओयो होटल के मुद्दे पर संवाददाता सम्मेलन किया। इस दौरान डिप्टी मेयर रविंद्र भारद्वाज और नेता सदन मुकेश गोयल भी उपस्थित रहे। मेयर महेश कुमार ने कहा कि अवैध स्पा, रेस्टोरेंट और ओयो होटल के मुद्दे पर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी समेत सभी 12 क्षेत्रों के उप स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की गई है और अवैध रूप से चल रहे उपरोक्त प्रतिष्ठानों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सभी अधिकारियों से 2 दिन के अंदर अवैध रूप से चल रहे स्पा, ओयो होटल व रेस्टोरेंट की सूची देने के भी निर्देश दिए गए हैं।

मेयर महेश कुमार ने कहा कि दिल्लीवासियों की शिकायत पर अवैध स्पा, ओयो होटल एवं रेस्टोरेंट के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेयर ने कहा कि अवैध रूप से संचालित स्पा ओयो होटल एवं रेस्टोरेंट किसी भी प्रकार का लाइसेंस शुल्क निगम को नहीं देते हैं, जिसके चलते निगम को राजस्व की हानि होती है। उन्होंने कहा कि हमने निगम के जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से ऐसे सभी प्रतिष्ठानों की जानकारी 2 से 3 दिनों के अंदर देने के लिए कहा है, ताकि इन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

यूजीसी के एडवांस इंक्रीमेंट रोकने समेत अन्य मांगों को लेकर डूटा का प्रदर्शन

नई दिल्ली, (हि.स.)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एडवांस इंक्रीमेंट रोकने और वसूली संबंधी स्पष्टीकरण पत्र के विरोध और अन्य मांगों को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने यूजीसी के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। देश भर के शिक्षक बड़ी संख्या में इस धरने में शामिल हुए। धरने को संबोधित करते हुए डूटा अध्यक्ष प्रो एके भागी ने कहा कि एडवांस इंक्रीमेंट स्पष्टीकरण पत्र को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। उन्होंने बताया कि पहले भी नवंबर 2017 में एमफिल और पीएचडी अग्रिम वेतन वृद्धि को रोकने के प्रयास किए गए थे लेकिन शिक्षकों के जबरदस्त विरोध के कारण यह संभव नहीं हुआ। गौरतलब है कि स्थाई रूप से नियुक्त शिक्षकों को एमफिल और पीएचडी की उपाधि के लिए प्रोत्साहन के रूप में एडवांस इंक्रीमेंट का प्रावधान चौथे वेतन आयोग में देना शुरू किया गया था। चौथे वेतन आयोग से लेकर सातवें वेतन आयोग में निरंतर केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम में इसे दिया जा रहा था लेकिन हाल ही में यूजीसी ने एडवांस इंक्रीमेंट स्पष्टीकरण पत्र 10 फरवरी को देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों को भेजा, जिसमें एमफिल और पीएचडी के लिए दी गई एडवांस इंक्रीमेंट को रोकने और वसूली संबंधी निर्देश दिए गए थे। इस स्पष्टीकरण में इंक्रीमेंट रोकने और वसूली को लेकर देशभर के शिक्षक आक्रोश में थे। प्रो एके भागी के नेतृत्व में दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने इस मामले में एक ज्ञापन यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश को सौंपकर इसे वापस लेने की मांग की थी। डूटा अध्यक्ष ने नवनियुक्त स्थाई शिक्षकों की पूर्ण पास्ट सर्विस को सर्विस में जोड़ने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार वित्त पोषित कॉलेजों की ग्रांट और वेतन की समस्या के स्थाई समाधान के लिए केंद्र सरकार को इनका अधिग्रहण करना चाहिए। इलाहबाद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय संघटक महाविद्यालय शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने भी धरने प्रदर्शन में भाग लेकर यूजीसी के आदेश को वापस लेने की मांग की। डूटा उपाध्यक्ष सुंधाशु कुमार और डॉ त्रिवेंद्र चुंबक ने कहा कि अगर शिक्षकों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में इस आंदोलन को तेज किया जाएगा।

बांसुरी स्वराज ने करोल बाग में 'जन औषधि केंद्र' का किया दौरा

नई दिल्ली, (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने शुक्रवार को 'जन औषधि दिवस' के मौके पर करोल बाग में 'जन औषधि केंद्र' का दौरा किया। उन्होंने बताया कि यह प्रधानमंत्री की दूरदर्शी परियोजना है।

बांसुरी स्वराज ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में लगभग 15 हजार 'जन औषधि केंद्र' खोले गये हैं। यह केंद्र लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

उन्होंने कहा कि यह जन औषधि केंद्र सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के साथ रोजगार का भी फायदा देता है। उन्होंने बताया कि जन औषधि केंद्र में दो हजार से ज्यादा अच्छी गुणवत्ता की सस्ती दवा मिलती है।

बांसुरी स्वराज ने कहा कि सरकार इन केंद्रों को फ्रेंचाइजी के आधार पर खोलने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों, महिलाओं, पूर्व सैनिकों और दलितों के लिए एक बड़ा अवसर है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने शुक्रवार को 'जन औषधि दिवस' के मौके पर करोल बाग में 'जन औषधि केंद्र' का दौरा किया।

Page-08_Layout 1 3/8/2025 2:23 AM Page 1

उत्तर प्रदेश का सामर्थ्य देख रही देश और दुनिया : योगी

दिव्य भारत संवाददाता

आगरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को आगरा सर्किट हाउस में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम-युवा) के तहत मंडल के 1000 युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के विकास, देश की प्रगति और नए भारत के विजन को रेखांकित किया। सीएम

- **युवा के तहत मंडल के 1,000 युवाओं को मुख्यमंत्री ने ब्याज मुक्त ऋण किया वितरित**
- **दो वर्ष के अंदर भारत बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था**
- **उत्तर प्रदेश पंच तीर्थ आज धर्म, आस्था के साथ-साथ आजीविका का बने आधार**
- **इनोवेशन और विजन के साथ टेक्नोलॉजी मिल जाए, तो समृद्धि आने से कोई रोक नहीं सकता**
- **अगले वर्ष तक 20 लाख युवाओं को रोजगार देगी योगी सरकार**
- **मुख्यमंत्री ने आगरा में मेट्रो कार्य का भी किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश**

योगी ने इस दौरान राज्य को माफिया मुक्त और दंगा मुक्त बनाने के साथ- साथ युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देख रही है। उन्होंने कहा कि इनोवेशन और विजन के साथ टेक्नोलॉजी मिल जाए तो समृद्धि आने से कोई रोक नहीं सकता।

अपने संबोधन की शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि होली के रंगोत्सव को बरसाना में शुरू करने के बाद मुझे आप सभी युवा साथियों के साथ मिलने का मौका मिला है। आप देश की आधारशिला रखने वाले हैं। उन्होंने 1,000 नए उद्यमियों को बधाई देते हुए कहा कि ये युवा देश और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश का सामर्थ्य आज देश और दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत ने विकास की नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। अब हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, जो संस्कृति और समृद्धि, विरासत और विकास, आस्था और आजीविका का अद्भुत संगम प्रस्तुत कर रहा है।

सीएम योगी ने पीएम मोदी के विजन को दोहराते हुए कहा कि नए भारत में भेदभाव किसी के साथ नहीं है। सुरक्षा सबको, समृद्धि सबको, आगे बढ़ने के अवसर सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। उन्होंने हाल ही में प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ का उदाहरण देते हुए कहा कि 45 दिनों में 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में डुबकी लगाई। यह आयोजन स्वच्छता, सुरक्षा और आजीविका के समन्वय का प्रतीक बना। उन्होंने बताया कि महाकुंभ ने उत्तर प्रदेश को पांच आस्था कॉरिडोर दिए हैं- प्रयागराज से विंध्यवासिनी धाम, काशी, अयोध्या, गोरखपुर, ऋंगवेरपुर धाम, लखनऊ, नैमिषारण्य, चित्रकूट और आगरा, मथुरा, वृंदावन, बरसाना होते हुए शुक तीर्थ तक। ये कॉरिडोर आस्था के साथ-साथ आजीविका का आधार बन रहे हैं।

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी युवा आबादी है, जो 56-60% कामकाजी तबके की है। ये युवा ऊर्जा से भरपूर और प्रतिभा संपन्न हैं। इन्हें सही अवसर मिले तो ये देश और दुनिया को नेतृत्व दे सकते हैं। इसी उद्देश्य से 24 जनवरी 2025 को शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत युवाओं को स्टार्टअप और स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण और मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि योजना शुरू होने के डेढ़ महीने के भीतर ही 1.5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 25,000 को स्वीकृति मिल चुकी है और 10,000 को ऋण वितरित हो चुका है। सीएम ने बताया कि गोरखपुर और बस्ती मंडल में कल 2,500 युवाओं को ऋण वितरित किया गया, जबकि आगरा में पहले भी एक कार्यक्रम हो चुका है। आज फिर 1,000 युवाओं को ऋण वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि हमारा युवा अब नौकरी के पीछे नहीं भागेगा, बल्कि नौकरी पैदा करेगा और लोगों को स्वावलंबन के रास्ते पर ले जाएगा।

सीएम योगी ने भारत के ऐतिहासिक और वर्तमान आर्थिक परिदृश्य का उल्लेख करते हुए कहा कि 16वीं सदी तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का 30% योगदान था। विदेशी आक्रांताओं और अंग्रेजों ने इसे लूटा, जिसके कारण 2014 तक भारत 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रह गया था। लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के जरिए भारत आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अगले दो वर्षों में हम तीसरे स्थान पर होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से देश की जीडीपी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और हर हाथ को काम मिलेगा। नया भारत, विकसित भारत फिर से दुनिया को नेतृत्व देगा। उन्होंने युवा उद्यमियों से धैर्य के साथ कार्य करने और इस योजना का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक हम 1 लाख युवाओं को ऋण देंगे और 1 अप्रैल से अगले 1 लाख युवाओं को जोड़ेंगे। इससे अगले साल तक 20 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब निवेश और पर्यटन के नए गंतव्य के रूप में उभर रहा है। 33 सेक्टोरियल पॉलिसी के जरिए लाखों करोड़ का निवेश आ रहा है और लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बन रहे हैं। उन्होंने महाकुंभ और बरसाना की लड्डूमार व लट्ठमार होली का जिक्र करते हुए कहा कि ये आयोजन सौहार्द और एकता का संदेश दे रहे हैं। अंत में, सीएम योगी ने सभी युवा उद्यमियों को बधाई देते हुए कहा कि होली आपके जीवन में उत्साह और उमंग का संचार करे। उन्होंने युवाओं के जज्बे, विजन और इनोवेशन की सराहना की और कहा कि यह नया उत्तर प्रदेश और नया भारत समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम में युवा उद्यमियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को भी सीएम ने देखा और उनके प्रयासों की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में मेट्रो के कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

शक्ति रसोई सशक्त होती महिलाएं, बदलती ज़िंदगियां।

मायावती ने धामी सरकार की आलोचना की

लखनऊ, (हि.स.)। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने उत्तराखंड में मजारों एवं मदरसों पर कार्रवाई को लेकर राज्य की धामी सरकार की आलोचना की है। मायावती ने शुक्रवार को एक्स पोस्ट में कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पहले कुछ मजारों व धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किए जाने के बाद अब राजधानी देहरादून में 11 प्राइवेट मदरसों को सील किए जाने की खबर काफी चर्चा में है।

सरकार को धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली ऐसी द्वेषपूर्ण व गैर सेक्युलर कार्रवाइयों से बचना चाहिए। मायावती ने एक अन्य पोस्ट में 15 मार्च को कांशीराम की जयंती पूरे मिशनरी भावना के साथ मनाने की अपील।

संक्षिप्त समाचार

संभल में जुमे पर चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात

संभल, (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। विवादित स्थल जामा मस्जिद के आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इलाके के सभी संवेदनशील चौक-चौराहों पर सुरक्षा की दृष्टि से विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने मीडियाकर्मियों को बताया कि विवादित स्थल पर जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने के लिए श्री लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गयी है। संदिग्ध व्यक्तियों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। पुलिस बल और पीएसी की तैनाती करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सभी मजिस्ट्रेट को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सदर कोतवाली और नखासा क्षेत्र में अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस और पीएसी के जवान तैनात हैं और हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। रमजान और होली के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराये जाने को लेकर गुरुवार को क्षेत्राधिकारी अनुज चौधरी ने बैठक की। उन्होंने कहा कि साल में 52 बार जुमा आता है, लेकिन होली एक दिन। अगर किसी को होली के रंग से दिक्कत हो तो वह घर से बाहर न निकले।

मुख्यमंत्री आवास के पास परिवार ने आत्मदाह का प्रयास किया

लखनऊ, (हि.स.)। लखनऊ में काली मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास के पास लामार्ट चौराहे पर शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब परिवार के साथ पेट्रोल डालकर पहुंचे युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिस ने पानी डाला ताकि उसे बचाया जा सके। पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। पीड़ित युवक राजन मिश्रा ने पुलिस को बताया कि वह मूलरूप से प्रतापगढ़ जिले में राजनीगंज फटनपुर सुरवा मिश्रपुर की रहने वाले हैं। उनका आरोप है कि गांव के शारदा प्रसाद, हरिशंकर, प्रेमनारायण समेत कई लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से भी मदद मांगी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही हैं। थाना, जिला प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाकर थक चुके हैं, इसलिए आज वह अपने परिवार संग आत्मदाह के लिए यहां पहुंचे थे। परिवार में पत्नी रेखा, दो बेटियां थी। गौतमपल्ली थानाध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास के पास एक परिवार द्वारा आत्मदाह का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार से जानकारी लेकर जिले के संबंधित थाना को सूचित कर दिया गया है।

प्रेमिका के पति की हत्या में मकान मालिक गिरफ्तार

गाजियाबाद, (हि.स.)। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में एक मकान मालिक ने प्रेमिका के पति का पत्थर से सिर कूचकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्याकांड में आरोपित मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने शुक्रवार को बताया कि थाना इंदिरापुरम अंतर्गत लोकप्रिय विहार खोडा कॉलोनी निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति मुहम्मद जलाल की अज्ञात व्यक्ति ने ग्रीन पार्क प्रथम इंदिरापुरम में हत्या कर दी। पुलिस टीमों ने जांच कर नूरानी मस्जिद के पास आरोपित मुहम्मद इबादत उर्फ इब्बे को गिरफ्तार कर लिया। एसीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित से पूछताछ में पता चला कि मृतक जलाल पत्नी के साथ उसके मकान में किराये पर रहता था। इस दौरान मृतक की पत्नी से उसके प्रेम संबंध हो गये। बीते दिनों इसकी जानकारी मृतक को हो गयी। जिसके बाद से उसकी पत्नी ने मुझसे बातचीत करना बन्द कर दिया।कुछ दिन पूर्व जब उसने जलाल से किराया मांगा तो उसने अपमानित किया। इस बात ने आक्रोशित होकर उसे रास्ते से हटाने की ठान ली। साजिश के तहत ही 5 मार्च को पान खिलाने के बहाने जलाल को घर से बाहर ले गया। इस दौरान उसे शराब पिलाई और मौका पाकर पत्थर से सिर पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त पत्थर उसकी निशानदेही पर बरामद करते हुए आरोपित के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

दिल्ली एनसीआर में सक्रिय शातिर चेन लुटेरा सोनूबाल्मीकि पुलिस मुठभेड़ में हुआ लंगड़ा

गाजियाबाद, (हि.स.)। थाना मधुबन बापूधाम पुलिस ने गुरुवार की रात में मुठभेड़ के दौरान दिल्ली एनसीआर में सक्रिय शातिर स्नैचर के पैर में गोली लगी है जब पुलिस उसे बरामदगी के लिए ले जा रही थी। और वह लंगड़ा हो गया है। उसके कब्जे से 01 तमंचा, 01 खोखा कारतूस, एक लूटा गया मोबाइल फोन व स्नेचिंग की गई चैन को बेचकर प्राप्त 3400 रुपये बरामद हुए है। लुटेरा शाहपुर मुरादनगर निवासी सोनू उर्फ सोनी वाल्मीकि उर्फ सोनू शाहपुरिया। है। एसीपी स्वतन्त्र कुमार ने बताया कि थाना मधुबन बापूधाम पुलिस ने चौकी क्षेत्र सैक्टर 23 में महिला से जीआर फार्म हाउस के पास से चैन स्नैचिंग करने, तथा चौकी क्षेत्र मधुबन बापूधाम से 21 जनवरी को मटियाला कट से मोबाइल लूट करने तथा थाना सिहानी गेट में एक महिला से ग्रान्ड पेन्टल बैन्कट के पास से चैन स्नैचिंग करने वाले सोनू उर्फ सोनी वाल्मीकि उर्फ सोनू शाहपुरिया को मैनापुर रोड से गिरफ्तार किया था।

महिलाओं के प्रति समर्पण और सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही योगी सरकार

आशीष पाण्डेय /दिव्य भारत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए पिछले आठ वर्षों में अनेक पहल की हैं। विगत वर्षों में शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और अभियानों के माध्यम से राज्य सरकार ने आधी आबादी को न केवल सम्मान और सुरक्षा प्रदान की, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में भी ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इन प्रयासों की झलक बजट 2025-26 में भी देखने को मिली, जिसमें महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के लिए कई नई घोषणाएं की गई हैं। महिलाओं के प्रति यह समर्पण न केवल उत्तर प्रदेश के विकास को गति दे रहा है, बल्कि देश के सामने एक मिसाल भी पेश कर रहा है।

योगी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के तहत लगभग 09 लाख व्यक्तिगत और 69 हजार से अधिक सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कर सभी नगरीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने में सफलता हासिल की है। खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए 1,100 ब्लॉकों में पिंक शौचालयों का निर्माण कराया गया है। यह कदम महिलाओं के सम्मान और उनकी गरिमा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

- **योगी सरकार ने महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा और सशक्तीकरण के लिए पिछले आठ वर्षों में की हैं अनेक पहल**
- **विभिन्न योजनाओं और अभियानों के माध्यम से सरकार ने आधी आबादी को दिलाया सम्मान और सुरक्षा**
- **महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में भी उठाए गए ऐतिहासिक कदम**
- **बजट 2025-26 में भी महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के लिए की गई हैं कई नई घोषणाएं**

कमजोर वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को उच्चीकृत किया गया है, जहां कक्षा 12 तक मुफ्त आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं, शादी अनुदान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 करोड़ रुपये के प्रावधान से दिसंबर 2024 तक 58,594 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया जा चुका है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से अब तक 22 लाख 11 हजार बालिकाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने का कार्य किया गया है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 2016-17 में जहां 17 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा था, वहीं 2023-24 में यह संख्या बढ़कर 34 लाख हो गई है। इन महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की पेंशन प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, अनुपूरक पुष्टाहार योजना के जरिए 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती-धात्री महिलाओं के लिए पोषण सुनिश्चित करते हुए 2 करोड़ 12 लाख लाभार्थियों के जीवन में सुधार किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 2024-25 से दो मुफ्त सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं के घरेलू जीवन में सुगमता आई है। रक्षाबंधन के पर्व पर 2017 से 2024 तक 1 करोड़ 20 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की गई।

प्राथमिकता से 10 बड़े बकायेदारों से वसूली करायी जाये : जिलाधिकारी

दिव्य भारत संवाददाता

प्रतापगढ़। जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय के सभागार में शिव सहाय अवस्थी की अध्यक्षता में में राजस्व प्रशासन एवं कर-करेत्तर राजस्व संग्रह की समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी द्वारा पिछली बैठक में दिये गये निदेर्शों के अनुपालन के सम्बन्ध में समीक्षा भी की गयी।

जिसमें तहसीलदारों को निर्देशित किया गया था कि परिवहन के 10 बड़े बकायेदारों की सूची लेकर बैठक में प्रतिभाग करें जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने तहसीलदार कुण्डा से जानकारी ली तो उनके द्वारा बताया गया कि बड़े बकायेदारों की सूची लेकर नही आये है और पिछले बैठक के कार्यवृत्ति की जानकारी भी नही थी। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा तहसीलदार कुण्डा को कड़ी फटकार लगायी और समस्त तहसीलदारों को मौखिक चेतावनी देते हुये कहा कि पत्रों को पढ़ना सीखे जो भी निर्देश दिये जाये उसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

पिछली बैठक में परिवहन विभाग को दिये गये निदेर्शों के अनुपालन के सम्बन्ध में एआरटीओ प्रवर्तन से पूछे जाने पर कोई भी स्पष्ट जवाब नही दिया गया, न ही दिये गये निर्देश पर कोई कार्यवाही नही की गयी जिस पर जिलाधिकारी ने एआरटीओ प्रवर्तन दिलीप कुमार गुप्ता को कड़ी फटकार लगाते हुये मौखिक चेतावनी दी और कहा कि अगली बैठक में दिये गये निदेर्शों पर कार्यवाही कराते हुये बैठक में आये। डीएफओ से जानकारी ली गयी कि जनपद में कितनी आरा मशीनें है तो बताया गया कि 148 आरा मशीनें पंजीकृत है जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि आरा मशीनों का सत्यापन करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

ब्रजेश पाठक ने महिलाओं को सम्मानित किया

अजीत प्रताप सिंह

लखनऊ। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और महापौर सुषमा खर्कवाल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर लखनऊ

महानगर महिला मोर्चा द्वारा हलवासिया कोर्ट में आयोजित ₹महिला सम्मेलन एवं महिला सम्मान समारोह₹ में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया।

मातृशक्ति को संबोधित करते हुए बृजेश पाठक ने कहा कि नारी शक्ति का सम्मान हमारी संस्कृति है इसी विचारधारा को हमारी सरकार ने आत्मसात किया है, महिलाओं के उत्थान, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए भाजपा सरकार निरंतर प्रतिबद्धता से कार्यरत है।

महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने नारी वंदन अधिनियम लागू करके महिलाओं को सम्मान देने का कार्य किया है। आज देश की, उत्तर प्रदेश की और लखनऊ की प्रथम नागरिक भी महिला है यह हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार में ही ऐसा संभव है। हमारी संस्कृति में भी सदैव से महिलाओं को ही पहले सम्मान दिया जाता है।

पट्टी तहसील में गोलीबारी

धर्मेन्द्र श्रीवास्तव

- **तहसील परिसर में राम भरोसो सुरक्षा**
- **एसडीएम पट्टी के चेंबर में चली गोली**
- **दो अधिवक्ताओं में विवाद होने पर चली गोली**

प्रतापगढ़/पट्टी। पुलिस की लाचार कार्यशैली और लापरवाह पुलिस कर्मचारियों के कारण पट्टी तहसील राम भरोसे चल रही है। तहसील परिसर में कोई भी बड़े ही आराम से असलहे को लेकर आ और जा सकता है,चेकिंग करने के लिए कोई भी पुलिसकर्मी नहीं रहता है। पुलिस की इसी लचर व्यवस्था के चलते एसडीएम की मौजूदगी में चेंबर में एक अधिवक्ता ने ही प्रतिद्वंदी अधिवक्ताओं पर पिस्टल से फायर कर दिया। एसडीएम चैंबर में गोली चलने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागता नजर आया। ये तो गनीमत हुई कि गोली चलने के बाद भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। गोली दीवार में जा लगी,गोली चलने की सूचना पर पट्टी कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची, आनन फानन में एसडीएम कोर्ट में पहुंचकर पुलिस जांच में जुट गई। दरअसल पट्टी तहसील में शुक्रवार को दिन में करीब 11:30 बजे एसडीएम पट्टी तनवीर अहमद अपने चेंबर में बैठे हुए थे। इस दौरान उनके चेंबर में अधिवक्ता मनीष तिवारी, बबलू,रवि सिंह,भास्कर तिवारी, सत्यम,प्रदीप पाठक,आशीष तिवारी,उमेश तिवारी आदि अधिवक्ता किसी मुकदमे को लेकर एसडीएम पट्टी से बातचीत कर रहे हैं थे। आरोप लग रहा है कि इस दौरान अधिवक्ता विकास श्रीवास्तव निवासी इलाही एसडीएम चेंबर में आया और किसी बात को लेकर अधिवक्ताओं में कहां सुनी होने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि विकास श्रीवास्तव ने पिस्टल निकालकर फायर करने वाला था कि वहां मौजूद किसी अधिवक्ता ने पिस्टल से फायर करने के दौरान ही उसने विकास का हाथ ऊपर कर दिया। जिससे गोली छत पर जाकर लगी। एसडीएम कोर्ट में गोली चलने की जानकारी होने पर तहसील में मौजूद अन्य अधिवक्ता भी मौके पर पहुंच जाते हैं। वहीं पट्टी पुलिस को जैसे ही एसडीएम कोर्ट में गोली चलने की सूचना मिलती है, पट्टी कोतवाल आलोक कुमार भारी फोर्स के साथ तहसील पहुंच जाते हैं। एसडीएम चैंबर से कारतूस का खोखा भी पुलिस को मिल जाता है। जो खोखा देखने से पिस्टल या रिवाल्वर का प्रतीत हो रही है। गोली चलने के समय हाथ ऊपर कर देने से एक बड़ी घटना घटने से बच गई। अगर गोली किसी को लग जाती तो एक बड़ी घटना हो जाती। वहीं अधिवक्ताओं के आक्रोश के चलते एसडीएम पट्टी चेंबर छोड़कर बाहर निकल गए।